वर्ष : 17 ❖ अंक : 258 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 26 अप्रैल 2023

40% वाली सरकार ने कर्नाटक को बेरहमी से लूटा : प्रियंका गांधी 3

कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे : अमित शाह 8

कंकाल मामला : पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

पूरे मामले की जांच जारी : एसपी लेप्चा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । सिक्किम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 14 वर्षीय लड़के दिवस गुरुंग का कंकाल मिलने की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सोमवार को दिवस का कंकाल मिला था। गंगटोक के एसपी टीएल लेप्चा और अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किशोर दिवस गुरुंग का कंकाल उनके लापता होने के लगभग नौ महीने बाद मिला।

एसपी लेप्चा के मुताबिक, किशोर दिवस गुरुंग 17 जुलाई, 2022 को लिंगडिंग, गंगटोक स्थित एक छात्रावास से लापता हो गया था और उसका कंकाल नौ महीने बाद 24 अप्रैल को गंगटोक के इंचे स्कूल के पास जंगल में मिला। अपने भाई के साथ स्कूल के हॉस्टल में रहने वाला दिवास गुरुंग 17 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे हॉस्टल से निकला था और आखिरी बार उसे चांदमारी में पेट्रोल पंप के पास देखा गया था। पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि उसने इसी दिन आत्महत्या की हो।

पुलिस का कहना है कि सिर्फ कंकाल मिला है और चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए मृतक की मां के बयान के आधार पर किशोर के आत्महत्या के कोण से जांच की जा रही है। वहीं लड़के की पतलून भी एक पेड़ पर लटकी मिली, जिससे कहा जा रहा है कि यह घटना आत्महत्या हो सकती है। इस बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है और कंकाल का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है।

एसपी लेप्चा के अनुसार दिलीप गुरुंग और सुशीला गुरुंग का पुत्र दिवस गुरुंग लिंगडिंग स्कूल का छात्र था और अपने छोटे भाई के साथ स्कूल के छात्रावास में रहता था। पुलिस के मुताबिक मृतक की मां के बयान के आधार पर दिवास गुरुंग के लापता होने के डेढ़ महीने पहले से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था। चिड़चिड़ापन, अकेले रहना पसंद करने और बार-बार घर में बीमार रहने की शिकायत के बाद उसे 22 अप्रैल 2022 को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था और आंखों की जांच, सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट सामान्य थी।

उन्होंने बताया कि नौ महीने बाद, स्थानीय सड़क पर काम कर रहे लोगों ने जंगल में एक कंकाल देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने कहा कि जब उन्होंने जांच की, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिवस गुरुंग ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने कहा है कि वह घटना की जांच जारी रखे हुए है।

एकजुट होकर संकल्प के साथ बढ़े आगे : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इन दिनों अपने 5 दिवसीय उत्तर सिक्किम के दौरे पर हैं। इसी सन्दर्भ में आज वे लाचुंग के जुमसा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें सिक्किम के सड़क एवं पुल मंत्री एवं क्षेत्र विधायक श्री सामडुप लेख्रचा, लाचुंग पिपन पेमा वांगदी लाचुंग्पा और दोरजे छेवांग लांचुंग्पा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के आरंभ में जुमसा प्रणाली एवं पिपन की गतिविधियां कराई गई। इसके बाद राज्यपाल द्वारा स्थानीय लोगों को कंबल और सिलाई की मशीन का वितरण किया गया। क्षेत्र विधायक ने राज्यपाल के अपने क्षेत्र में भ्रमण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राज्यपाल ने लोगों के साथ परस्पर बातचीत कर उनकी उपलब्धि और समस्याओं से अवगत हुए।

राज्यपाल ने कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों के साथ परस्पर बातचीत कर राज्य और केंद्र की कई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय लोगों से परस्पर बातचीत कर उनकी जीवनशैली से परिचित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विषम परिस्थितियों में प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर जीने की कला इनसे सीखनी चाहिए। उन्होंने लाचुंग वासियों को अभिनंदन और प्रेम भरे आतिथ्य भाव के लिए उनका आभार भी प्रकट किया।

राज्यपाल ने स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा का संवर्धन और संरक्षण करने की दिशा में कर रहे कार्य को सराहनीय बताया। उन्होंने सभी से एकीकृत प्रयासों और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अपील की।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । सिक्किम में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की स्थिति की समीक्षा हेतु केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज यहां ताशीलिंग सचिवालय में विभिन्न संबंधित विभागों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने अपने संक्षिप्त संबोधन में विभिन्न विभागों द्वारा सराहनीय कार्य किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की और स्वास्थ्य क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धस्तर पर काम करने का अनुरोध किया। इस सम्बंध में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आश्वासन दिया।

राज्य के ग्रामीण विकास आयुक्त सह सचिव डी आनंदन ने विभाग द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय योजनाओं की प्रस्तुति देते हुए मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिक्किम ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना समेत कई अन्य के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा, उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में सिक्किम एसआरएलएम की योजनाओं एवं गतिविधियों के बारे में भी बताया।

वहीं राज्य पुलिस के महानिरीक्षक डीबी गिरी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली, छात्र पुलिस कैडेट, मानव तस्करी विरोधी इकाई, निर्भया कोष के तहत (शेष पृष्ठ ०३ पर)

सिक्किम से कनेक्टिविटी को बनाया जाएगा आसान : अजय कु. मिश्रा

अनुगामिनी नि.सं.

नामची, 25 अप्रैल । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज नामची जिला प्रशासनिक केंद्र में विभिन्न विभाग प्रमुखों, पूर्व सैनिकों और अन्य स्थानीय लोगों के साथ एक चर्चा सत्र की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर नामची डीसी एम. भरणी कुमार, एसपी मनीष वर्मा, जिला अध्यक्ष सुश्री अंजीता राई और नामची नगर परिषद उपाध्यक्ष सुश्री सावित्री तामंग के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने पर्यटन, शिक्षा एवं समग्र प्रबंधन के क्षेत्र में सिक्किम को अपार संभावनाओं वाला बताते हुए यहां केंद्र सरकार की भावी विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भविष्य में सिक्किम से कनेक्टिविटी को आसान बनाया जाएगा और जल्द ही राज्य रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। वहीं उन्होंने जैविक खेती के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिए राज्य की सराहना की केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावी रूप से ऐसी योजनाओं को विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं जो जनता के दैनिक जीवन को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकें। इसके तहत उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम एवं अन्य का जिक्र किया।

इस दौरान नामची डीसी एम भरणी कुमार ने जिले में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति और प्रगति रिपोर्ट का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के तहत सालगढ़ी में मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना, निपुण भारत कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री वन धन योजना और अन्य के बारे में जानकारी दी। वहीं एसपी मनीष वर्मा ने भी जिले के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक प्रस्तुति पेश करते हुए सुचारू कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों, सुझावों और सभी कदमों की रूपरेखा के बारे में बतायी। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा शुरू की गई 'तपाइको पुलिस' (आपकी पुलिस) नामक परियोजना के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर एक चर्चा सत्र का भी आयोजन किया गया।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने जैविक मिशन की सराहना की

सिक्किम कला व साहित्य महोत्सव के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 25 अप्रैल । आगामी 6 से 8 मई के बीच होने जा रहे एसकेएम विद्यार्थी प्रकोष्ठ तथा टीमवर्क आर्ट्स जयपुर साहित्य महोत्सव के सहयोग से योक्सम में सिक्किम कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसे लेकर आज जिलाधिकारी के साथ जिला पंचायत भवन में आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सिक्किम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र विधायक योक्सम टाशीडिंग सांगे लेख्रचा ने की। उनके साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री भीमहांग सुब्बा, लोक सभा संसद इन्द्र हांग सुब्बा, गेजिंग जिला अध्यक्ष डीएस लिम्बू, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी के विद्यार्थी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सोनाम छापेल शेरपा विभिन्न बोर्ड और संस्था के सलाकार, अध्यक्ष, गेजिंग जिला के विभिन्न विभाग के प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

बैठक के पहले चरण में महकमा अधिकारी संतोष आले ने स्वगत भाषण देते हुए कार्यक्रम के औचित्य के बारे में जानकारी दी। अपने संबोधन में सोनाम छोपेल शेरपा ने कहा कि एसकेएम विद्यार्थी संगठन और टीमवर्क आर्ट्स के सदस्य विभिन्न रचनात्मक कला और साहित्य की पहल के माध्यम से नई पीढ़ी को कला और साहित्य के प्रति रुचि जगाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ कला तथा साहित्य महोत्सव इस साल पश्चिम सिक्किम के योक्सम में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री पीएस गोले ने सिक्किम कला और साहित्य महोत्सव की अवधारणा की परिकल्पना की थी। उनसे चर्चा के बाद इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि योक्सम का काफी प्राचीन महत्व है और यह सिक्किम का प्रारंभिक राजधानी रहा है। कला और महोत्सव के माध्यम से योक्सम के प्रवर्द्धन करने की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए महोत्सव स्थल के रूप में इसका चयन किया गया है। कंचनजंघा राष्ट्रीय निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत आने के कारण योक्सम को युनेस्को ने विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित किया है इसलिए इसका प्रवर्द्धन जरूरी है। इस कार्यक्रम से पूरे योक्सम को फायदा होगा।

सभा को संबोधित करते हुए सांसद सुब्बा ने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कार्यक्रम पार्टी और सरकार का ही केवल न होकर हम सभी सिक्किमी नागरिक का है। उन्होंने विभिन्न विभागों को इसे लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में देश विदेश के अनेक विद्यार्थी, साहित्यकार और वक्ता आदि शामिल होंगे। यस कार्यक्रम के प्रमुख संरक्षक मुख्यमन्त्री स्वयं होंगे तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा मन्त्री गण इसके संरक्षक होंगे। उन्होंने सभी से अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का आग्रह किया। इसमें शामिल विभिन्न लोगों ने अपने सुझाव दिए।

सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट कम्युनिटीज कॉन्क्लेव 29 से

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । सिक्किम सरकार के सहयोग से सतत एवं लचीले समुदायों पर सी20 इंडिया 2023 वर्किंग ग्रुप का सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट कम्युनिटीज कॉन्क्लेव इसी महीने की 29 और 30 तारीख को यहां आयोजित होने जा रहा है। 29 अप्रैल को इसके उद्घाटन समारोह में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस अवसर पर युगांडा के राजदूत जॉयस किकाफुंडा, राज्य के भूमि राजस्व मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा एवं जी20 प्रधान समन्वयक विजय नांबियार, भी समारोह को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम में अमृता विश्व विद्यापीठम पुरी के अध्यक्ष स्वामी अमृतस्वरूपानंद पुरी और सी20 के सदस्य ट्रोइका भी मौजूद रहेंगे।

30 अप्रैल को कार्यक्रम के समापन समारोह में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अपना सम्बोधन रखेंगे। इसके अलावा समापन समारोह में भारत में गाम्बिया के राजदूत मुस्तफा जवारा और मणिपुर सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थोंगम बिस्वजीत सिंह भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके अलावा इसमें जी20 देशों के कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी शामिल होंगे।

जानकारी के अनुसार, इसका लक्ष्य दुनिया भर के जलवायु, पर्यावरण एवं ऊर्जा क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों को जी20 वैश्विक नेताओं के समक्ष अपने लक्ष्यों को व्यक्त करने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में 22 देशों से 200 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें शिक्षाविदें, पेशेवरों एवं नागरिक सामाजिक संगठनों को भी जी20 नीतिगत चर्चा में भाग (शेष पृष्ठ ०३ पर)

घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरु

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आज से राजधानी गंगटोक में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर तीन दिवसीय बुनियादी और मध्यवर्ती प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई।

कार्यक्रम की शुरुआत में एसएसडीएमए निदेशक प्रभाकर राई ने अपने स्वागत भाषण में सभी से राज्य के कुशल एवं व्यापक आपदा प्रबंधन आकलन में भाग लेने का आग्रह किया। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य राज्य के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करके नुकसान को कम करना है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में शीघ्र ही एनडीएमए मॉक ड्रिल के आयोजन की जानकारी दी। वहीं सहायक एनआईडीएम प्रोफेसर शेखर चतुर्वेदी ने ड्रिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश में सफल आपदा प्रबंधन इतिहास के बावजूद अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आधुनिक प्रतिक्रियाओं को अधिक गहन, कुशल, त्वरित एवं सुनियोजित बनाने की आवश्यकता बताई।

वहीं कार्यक्रम में अतिथि वक्ता प्रोफेसर चतुर्वेदी ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली को आपातकालीन कार्रवाई करने की आवश्यकता घटाने में उपयोगी साधन बताया। उन्होंने बेहतर योजना, उत्तरदायित्व और विश्लेषण हेतु कई प्रकार की कार्रवाइयों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण को महत्वपूर्ण बताया।

वहीं उन्होंने देश में आपदाओं के लिए एक प्रभावी, कुशल और व्यापक प्रतिक्रिया के तहत एनडीएमए द्वारा डीएम अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आईआरएस के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इसका संचालन उन उद्देश्यों से प्रेरित होना चाहिए जो सर्वोत्तम रणनीतियों तथा इन्हें लागू करने के उपायों की पहचान करने में सहायता करते हैं।

कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में राज्य के भूमि सुधार सचिव एवं राहत आयुक्त अनिल राज राई ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में सभी प्राकृतिक त्रासदियों से प्रभावी एवं जिम्मेदारीपूर्वक निपटने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उनके अनुसार, आपदाएं मानव निर्मित या प्राकृतिक हो सकती हैं, और इनकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण तथा लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले संकटों की निगरानी हेतु निवारक उपाय किए जाने पर जोर दिया।

इस कड़ी में उन्होंने सभी से पर्यावरण रक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में सरकार के साथ सहयोग का आग्रह किया।

इसके अलावा एसएसडीएमए के वाइस चेयरमैन प्रो विनोद शर्मा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में वक्तव्य रखा। उन्होंने आपदा प्रबंधन के महत्व और इसे रोकने हेतु सिक्किम द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बात की। इससे पहले, भूकंप के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में एक एसएसडीएमए की एक वीडियो भी दिखाई गई।

वहीं इस दौरान एक प्राकृतिक आपदा के बारे में एक चर्चा सत्र का भी आयोजन हुआ।

विश्व जिन विवादों में घिरा है, उनका हल भारत के पास : सीएम शिवराज

भोपाल, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव-एकात्म पर्व पर मंगलवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आचार्य शंकर ने चारों दिशाओं में भारत को जोड़ने का काम किया है। आज विश्व जिन विवादों में घिरा है, उनका हल भारत के पास है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अपने अद्वैत दर्शन के माध्यम से भारत ही कराएगा। आज विश्व जिन विवादों में घिरा है, उनका हल भारत के पास है। हमारा दर्शन विश्व शांति और विश्व-कल्याण का है। हमारी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवंतु सुखिन: की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा अद्वैत दर्शन कहता है कि प्रत्येक जड़ और चेतन में एक ही चेतना है। हर आत्मा में परमात्मा है। अहम् ब्रह्मास्मि। मैं और तुम एक हैं, सभी एक हैं। यह जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के दर्शन की गहराइयों में जाएं तो विश्व के सारे विवादों का हल भारत के पास है। जिस प्रकार हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं, उसी प्रकार समाज के भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं। पूरी धरती और और उस पर रहने वाले शरीर है, सामूहिक संकल्प (मेरा देश, देश भक्ति) मन है, संविधान बुद्धि है और सबका कल्याण आत्मा है। सबके कल्याण में ही सारे विवादों का हल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व की सारी विचारधाराएं इसी चिंतन से निकली हैं कि सुखी कैसे रहा जाए। पश्चिम दर्शन कहता है कि शरीर की आवश्यकता है पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। हमारा दर्शन कहता है कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय का सुख ही पूरा सुख है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख चार पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से प्राप्त होता है।

विशिष्ट अतिथि अखंड परमधाम के संस्थापक महामंडलेश्वर व युगपुरुष स्वामी परमानंद गिरि महाराज ने कहा कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रचार का काम मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हो गया है। आने वाले समय में इसे और बल मिलेगा। यह काम हम संतों का था जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे आकर बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कार्य सराहनीय है, उसे वह पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। सर्वसमाज को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वप्न में हमें आभास होता है कि सिर कट गया लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता। ऐसी वृत्ति मृत्यु के जागने से ही जाएगी। मृत्यु तो तप है, दुख से बाहर जाने का उपाय है। यदि हमने इस शरीर के रहते नहीं जगाया तो आगे कैसे संभव होगा, जो यह जान लेता है वह ब्राह्मण है। कमियों को दूर करके विश्व निर्माण का यह समय है। उन्होंने कहा कि नशे में हर चीज अच्छी लगती है, उसे जगाना होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉ. कांशीराम ने कहा कि आज यह प्रकल्प बड़ा स्वरूप ले रहा है, जो आने वाले समय में विश्व में फैलेगा। अद्वैत दर्शन की विश्व में चर्चा होगी। सिर्फ यही फिलॉसफी है, जिसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि व्यक्ति भले ही अलग हैं, लेकिन चेतना एक ही है। जिसे एकात्म का भाव हो गया वही जागृत हो गया। मुझमें, दूसरे में अंतर की भिन्नता जिस दिन खत्म हो गई उस दिन सारा समाज एक हो जाएगा।

हम किसी भी चुनौती का जवाब देने को तैयार : वीआर चौधरी

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। भारत के पास किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौतियों का जवाब उचित स्तर पर देने की क्षमता और इच्छाशक्ति है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की ओर से यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद और सीमा पार पाकिस्तान से आतंकवाद के बीच आई है। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि बीते कुछ दशकों के संघर्षों ने स्पष्ट रूप से भविष्य के सभी परिचालन (ऑपरेशन) के लिए पसंद के साधन के रूप में एयरोस्पेस ताकत की श्रेष्ठता को स्थापित किया है।

एक टेलीविजन समाचार चैनल की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अपनी समग्र युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई क्षमताओं को जोड़ने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास क्षमता हैं और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास इच्छाशक्ति है कि हम उस स्तर पर जवाब दे सकते हैं, जिसे हम उचित समझते हैं।

वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा, वर्दी में हम पुरुष और महिलाएं उस प्रतिक्रिया के अग्रणी हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस धार को यथासंभव तेज और घातक रखें। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि वायुसेना के पास 'स्वतंत्र रणनीतिक अभियानों' के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की अन्य सेवाओं और हथियारों के साथ समन्वित अभियान चलाने की अनूठी क्षमता है।

उन्होंने कहा, हम भविष्य के युद्धों में संयुक्त योजना और क्रियान्वयन की अनिवार्यता को समझते हैं और तीनों सेनाओं के प्रयासों को एकीकृत करने के इच्छुक हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उनके बल ने हाल ही में अपने ऑपरेशनल डॉक्टरीन को अपडेट और संशोधित किया है, ताकि इसे अगले दशक के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में संघर्षों ने स्पष्ट रूप से लगभग सभी आकस्मिक ऑपरेशंस के लिए पसंद के साधन के रूप में एयरोस्पेस शक्ति की श्रेष्ठता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है।

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच पारंपरिक बलों के लिए नई चुनौतियां भी पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान-आर्मेनिया संघर्ष में लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन का उपयोग और रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में सशस्त्र ड्रोन का व्यापक उपयोग भविष्य में आने वाली चीजों का संकेत है।

दिल्ली में फिर डरा रहा कोरोना, 6 की मौत

राजेश अलख

नई दिल्ली, 25 अप्रैल । दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,095 नए मामले सामने आये और छह लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 22.74 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दिल्ली में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,35,156 हो गई और छह मरीजों की मौत हो जाने के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26,606 हो गई है।

वहीं, दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पतालों में उपलब्ध कुल 7,975 बिस्तरों में से फिलहाल 318 पर मरीज भर्ती हैं। इससे पहले, दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 689 मामले सामने आये थे और तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि संक्रमण दर 29.42 प्रतिशत रही थी।

योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करें अधिकारी : सांसद सुब्बा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा ने गंगटोक जिला पंचायत गठन के बाद सोमवार को पूर्वी जिला पंचायत सभागार में पहली दिशा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें डीसी तुषार जी निखारे एवं जिलाध्यक्ष बलराम अधिकारी के अलावा निर्वाचित प्रतिनिधिगण, संबद्ध विभागीय अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत विभिन्न विभागों की प्रस्तुतियों के साथ हुई।

इस अवसर पर सांसद एवं दिशा के अध्यक्ष इंद्र हांग सुब्बा ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि विभागों की प्रस्तुतियों ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को बल दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्यों और संबद्ध विभाग अधिकारियों को जिले के विकास हेतु सामूहिक समन्वय करने की सलाह देते हुए आगे रानी खोला की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों से योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का आग्रह किया।

वहीं अपने संबोधन में डीसी तुषार निखारे ने कहा कि इस बैठक ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति को समझने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने जिले के समग्र विकास हेतु सहयोगी विभागों के सहयोग की सराहना करते हुए इस मंच को कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने में मदद करने वाला बताया।

वहीं बैठक में अपनी पहली प्रस्तुति में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त निदेशक ने अपशिष्ट प्रबंधन में भावी गतिविधियों पर जानकारी दी। उच्च ऊंचाई वाली झीलों के पानी की गुणवत्ता का नमूना लेने पर केंद्रित इस प्रस्तुति में एक सामान्य बीएमडब्ल्यू उपचार सुविधा की स्थापना और बेहतर सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद यूडीडी की अगली प्रस्तुति में उप सचिव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया। इसमें प्रसंस्करण संयंत्र, क्षमता और राज्य सरकार द्वारा की गई पहल शामिल रही।

इसमें पर्याप्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुपस्थिति और संगठित अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों की अनुपस्थिति पर चर्चा की गई। इसके अलावा, गंगटोक नगर आयुक्त ने गंगटोक मार्केट कॉम्प्लेक्स में कचरा प्रबंधन और ठोस कचरे को अलग करने में सहायक कंपोस्टिंग मशीनों पर बात की। इस अवसर पर एक खुली चर्चा भी हुई, जिसमें प्रतिक्रिया और संबंधित विषयों पर बातचीत की गई। बैठक में सिंगातम एमईओ, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, एडीसी विकास, जीडीजेडपी एसई, शिक्षा सीईओ, सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों ने भी विचार रखे।

सिक्किम पशुधन विकास बोर्ड का एक दिवसीय प्रजनन शिविर सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 25 अप्रैल । राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सिक्किम पशुधन विकास बोर्ड द्वारा सोमवार को सुमिन-लिंग्ज़े जीपीयू अंतर्गत अपर सुमिन वार्ड में एक दिवसीय प्रजनन शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में अतिरिक्त निदेशक सह गंगटोक जिला प्रमुख डा जेरुइया भूटिया, अतिरिक्त निदेशक सह एसएलडीबी सीईओ डा कर्मा डोमा भूटिया, सेंट्रल पांडाम उप निदेशक डा शेरिंग डिकी भूटिया और पशु चिकित्सा अधिकारी डा तेनजिंग लोबसांग भूटिया रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में अपर सुमिन वार्ड के 40 किसानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर डा जेरुइया भूटिया ने सिक्किम में पशुओं में गांठदार त्वचा रोग, पोर्सिन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी उभरती बीमारियों पर प्रकाश डालते हुए रोगों के ब्रूसेला जैसे जूनोटिक महत्व, इसके लक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पर जानकारी दी।

वहीं डा कर्मा डोमा भूटिया ने वैज्ञानिक एवं स्वच्छ कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक सेवा पर कृत्रिम गर्भाधान के लाभों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एआई से संबंधित गलत धारणाओं को दूर करने के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के तहत सिक्किम पशुधन विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही रियायती पशु बीमा योजना के बारे में किसानों को अवगत कराया।

इसके अलावा, डा छिरिंग डिकी भूटिया ने विभिन्न प्रजनन विकारों जैसे बार-बार प्रजनन, साइलेंट हीट, एनेस्ट्रस, डायस्टोसिया, पशुधन को प्रभावित करने वाले प्लेसेंटा की अवधारण, पशुओं के प्रजनन एवे स्वास्थ्य, खनिजों एवं विटामिनों के महत्व पर बात की।

वहीं डा तेनजिंग लोबसांग भूटिया ने पारंपरिक जमे हुए वीर्य के उपयोग की तुलना में सेक्स सॉर्टेड वीर्य और इसके लाभों के बारे में बात की।

6 माइल, सामदुर, तादोंग- 737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन : 03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स: 251067
वेबसाइट : www.cus.ac.in

6th Mile, Samdur, Tadong – 737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph.: 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

SU/REG/Acad/F-1/13/2023/Vol-VII/ दिनांक : 04.2023

प्रवेश सूचना

सिक्किम विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित विभागों में प्रमाणपत्र, स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की घोषणा करता हैं।

1. मानवशास्त्र (एमए/एम.एससी/पीएच.डी)
2. भूटिया (एमए)
3. वनस्पति विज्ञान (एम.एससी/पीएच.डी)
4. रसायनिकी (एमएससी/पीएच.डी)
5. चीनी (प्रमापत्र, बीए, एमए)
6. वाणिज्य (एम.कॉम/पीएच.डी)
7. कम्प्यूटर अनुप्रयोग (एमसीए/पीएच.डी)
8. अर्थशास्त्र (एमए/पीएच.डी)
9. शिक्षा (एमए, एम.एड, पीएच.डी)
10. अंग्रेजी (एमए, पीएच.डी)
11. भूगोल (एमए/एम.एससी, पीएच.डी)
12. भूविज्ञान (एम.एससी और पर्यावरण विज्ञान में एम.एससी/पीएच.डी)
13. हिन्दी (बीए, एमए)
14. इतिहास (एमए, पीएच.डी)
15. उद्यानिकी (एम.एससी, पीएच.डी)
16. अंतरराष्ट्रीय संबंध (एमए, पीएच.डी)
17. विधि (एलएलएम, पीएच.डी)
18. लेप्चा (एमए)
19. पुस्तकालय विज्ञान (एम.लिब. आई. एससी)
20. 20. लिम्बू (एमए)
21. प्रबंधन (एमबीए, पीएच.डी)
22. जनसंचार (एमए, पीएच.डी)
23. गणित (एम.एससी, पीएच.डी)
24. सूक्ष्म जीविज्ञान (एम.एससी, पीएच.डी)
25. संगीत (बीपीए, एमपीए, पीएच.डी)
26. नेपाली (एमए, पीएच.डी)
27. शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंध्सन (एमए, पीएच.डी)
28. भौतिकी (एम.एससी, पीएच.डी)
29. राजनीति विज्ञान (एमए)
30. मनोविज्ञान (बीए/बी.एससी, एमए/एम.एससी, पीएच.डी)
31. समाजशास्त्र (एमए, पीएच.डी)
32. पर्यटन (एमटीटीएम, पीएच.डी)
33. प्राणीविज्ञान (एम.एससी, पीएच.डी)

सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रमाणपत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूईटी अंक अनिवार्य है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट **(https://www.cus.ac.in)** पर दिनांक **11.06.2023 से 20.06.2023 (मध्यरात्रि तक)** में उपलब्ध रहेगा। (सीयूईटी परिणामों के विलंब से प्रकाशन के कारण पंजीकरण तिथियों में होने वाले कोई भी परिवर्तन के बारे में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा)

पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की बेबसाइट **(https://www.cus.ac.in)** पर **28.04.2023 से 27.05.2023 (मध्यरात्रि तक)** तक उपलब्ध रहेगा।

प्रवेश के लिए पात्रता, सीटों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया और प्रवेश कैलेंडर के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम विवरणिका को देखें।

हस्ता./-
कुलसचिव

CBC 21318/12/0001/2324

रिजल्ट जारी करने में यूपी बोर्ड ने बनाया रिकॉर्ड, सीएम योगी ने दी बधाई, बोले- टॉप10 होंगे सम्मानित

लखनऊ, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) बोर्ड 25 अप्रैल, 2023 यानी मंगलवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में महज 67 दिनों में यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल घोषित करके 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जारी नतीजों में हाईस्कूल के 89.78 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 75.12 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है।

सीएम योगी ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षाओं में राज्य स्तर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 में आने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने की भी घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि घोषिण परीक्षाफल के अनुसार हाईस्कूल में कुल 179 छात्रों ने टॉप-10 में जगह बनाई है, तो इंटर में यह संख्या 253 है। दोनों परीक्षाओं में कुल 432 छात्र टॉप-10 में शुमार रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात ये है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई के 1 दिन बाद 16 फरवरी से शुरू हुई थी लेकिन यूपी बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई से पहले घोषित कर दिया गया, वह भी तब जब सीबीएसई की तुलना में यूपी बोर्ड में कई गुना छात्र अधिक हैं।

मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक महेंद्र देव और सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित करते हुए इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव ने बताया कि हाईस्कूल में सीतापुर की प्रियांसी सोनी ने 600 में 590 अंक लाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं, इंटर में महोबा के शुभ छापरा 500 में 489 अंक के साथ शीर्ष पर रहे हैं। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 100 वर्षों के इतिहास में सबसे पहले परीक्षाफल घोषित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है।

उन्होंने बताया कि 1921 में बोर्ड के गठन के बाद पहली बार 1923 में बोर्ड परीक्षा का संचालन किया गया था। तब से अब तक सबसे कम समय में बोर्ड ने परीक्षाफल घोषित किया है। इससे पहले 2019 में सबसे कम समय में 27 अप्रैल को परीक्षाफल की घोषणा हुई थी। तब 7 फरवरी से परीक्षा की शुरूआत हुई और 89 दिन में परीक्षाफल घोषित किया गया। इस बार 16 फरवरी के बाद परीक्षाएं आयोजित कराई गईं और कुल 67 दिन में परीक्षाफल घोषित कर दिया गया।

दिव्यकांत शुक्ल ने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप इस वर्ष बोर्ड ने नकल विहीन परीक्षा कराने में सफलता प्राप्त की थी। 30 वर्षों में यह पहला अवसर रहा जब कोई पेपर न तो वायरल हुआ, न ही रांग ओपनिंग हुई, न ही कोई परीक्षा रद्द की गई और न ही सामूहिक नकल हुई। उन्होंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड होने के नाते यह गौरव की बात है कि विगत 100 वर्ष में यह पहला अवसर है जब सारे रिजल्ट पूर्ण हैं। पहले किसी न किसी वजह से कुछ रिजल्ट अपूर्ण रह जाते थे। उन्होंने बताया कि परीक्षाफल घोषित होने के बाद अब ग्रीवांस सेल छात्रों की समस्याओं का निराकरण करेगा। सभी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ग्रीवांस सेल खोले गए हैं, जो अगले सप्ताह से कार्य करना शुरू कर देंगे। प्रार्थना पत्र देने वाले छात्रों की समस्याओं का यहां समयसीमा के अंदर निराकरण होगा। सोमवार के बाद स्क्रूटनी के आवेदन का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल रहे सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को मंगलवार को बधाई दी और कहा कि राज्य तथा जिल स्तर पर शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी ने एक बयान में सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देने के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा, हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभागार में वर्ष 2023 की हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करते हुए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि पिछले 100 वर्षों के इतिहास में सबसे पहले 25 अप्रैल 2023 को परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए।

मेरे पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता : न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय

कोलकाता, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी, बाद में गंगोपाध्याय ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह अपने पद से हट रहे हैं।

मंगलवार को दोपहर से पहले न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के अदालत में पेश नहीं होने के बाद कयासों को बल मिला। हालांकि, वह दोपहर के बाद कोर्ट में आए और एक सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि उनके पद छोड़ने की सभी अटकलें निराधार हैं।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, 'इस तरह की अटकलें निराधार हैं। जो लड़ाई शुरू हुई है, वह जारी रहेगी। चूंकि मैंने साक्षात्कार दिया है, इसलिए मुझे अपना स्पष्टीकरण भी देना होगा। शीर्ष अदालत का आदेश अभी अपलोड होना बाकी है। आने दीजिए, मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा।'

उन्होंने पहले दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे कुछ वकील उनके बारे में शीर्ष अदालत को गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ ऐसी शिकायत दर्ज की गई है, जो उन्होंने कभी नहीं कही।

प्रधान न्यायाधीश ने सोमवार को कहा था कि कोई न्यायाधीश किसी भी समाचार चैनल को साक्षात्कार नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ न्यायाधीशों को साक्षात्कार के दौरान किसी याचिकाकर्ता के बारे में बोलते सुना गया है, जो अनुचित है।

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट भी मांगी और रजिस्ट्रार जनरल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय से व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापित करवाने का निर्देश दिया कि क्या उनका साक्षात्कार लिया गया था? अगर लिया गया था तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को सुप्रीम कोर्ट के ज्युडीशियल रजिस्ट्रार के समक्ष शुक्रवार को हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

पीएफआई फुलवारीशरीफ मामले में छापेमारी के बाद एनआईए ने बरामद किए सबूत

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ दर्ज फुलवारीशरीफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को चार राज्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। संदिग्धों द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित मामले में पीएफआई संदिग्धों के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान बैंक लेनदेन विवरण के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का एक जखीरा जब्त किया गया।

अधिकारी ने कहा- ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, एनआईए की टीमों ने बिहार के सीवान, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिलों, गोवा के दक्षिण गोवा जिले, उत्तर प्रदेश के रामपुर और भदोही जिलों और पंजाब के लुधियाना जिले में कई स्थानों पर 16 संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की।

पीएफआई और 1,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के साथ भारतीय मुद्रा से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। पटना के फुलवारीशरीफ में 6 और 7 जुलाई, 2022 को पीएफआई कैडर के प्रशिक्षण से जुड़े मामले में कुछ अन्य संदिग्धों के साथ अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र करने के लिए अब तक कुल 60 स्थानों की तलाशी ली जा चुकी है। एजेंसी ने 7 जनवरी, 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

जांच से पता चला है कि आरोपी, अन्य संदिग्धों के साथ, पीएफआई की ओर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए फुलवारीशरीफ में किराए के परिसर से काम कर रहे थे। उन्होंने पीएफआई के भर्ती किए गए कैडरों के लिए शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया था। यह भी संदेह है कि सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी इसके कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा और इसकी नापाक, गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल रहे।

सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट .....

लेने का मौका मिलेगा। यह कॉन्क्लेव सिक्किम को जी20 मानचित्र में सतत और लचीले प्रथाओं में निहित राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

सिक्किम के भू-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव अनिल राज राई ने कॉन्क्लेव के बारे में बताया कि गंगटोक में यह सी20 कॉन्क्लेव जी20 देशों के नागरिक सामाजिक संगठनों के लिए कई दबाव वाले मुद्दों पर सामूहिक रूप से अपनी चिंताएं व्यक्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। वहीं सी20 इंडिया वर्किंग ग्रुप कोऑर्डिनेटर और अमृता विश्व विद्यापीठम की प्रोवोस्ट डॉ. मनीषा सुधीर ने कहा कि सी20 चेयर श्रीमाता अमृतानंदमयी देवी के निर्देशन में इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य नागरिक सामाजिक संगठनों और दुनिया भर के प्रतिनिधियों के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह जलवायु लचीलापन, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रबंधन के क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए गहन संवादों के माध्यम से समुदायों को सतत एवं लचीला बनाने में मदद करेगा।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री .....

महिला सहायता डेस्क एवं अन्य पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय को राज्य में ईआरएसएस की स्थिति के बारे में भी बताया और पुलिस विभाग द्वारा उपकरणों की खरीद के बारे में जानकारी दी। उनके अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रधान निदेशक सह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध निदेशक डॉ. अनुषा लामा ने मंत्री को सिक्किम में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया।

इसके अलावा, खेल व युवा मामलों के विभागीय प्रमुख निदेशक सह बीएडीपी राज्य नोडल अधिकारी सुश्री सुचित्रा थापा, समग्र शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी डीवी बसनेत ने भी अपनी विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में अतिरिक्त गृह मुख्य सचिव ए सुधाकर राव, शिक्षा एसीएस आर तेलंग, डीजीपी एके सिंह एवं अन्य भी उपस्थित रहे।

40% वाली सरकार ने कर्नाटक को बेरहमी से लूटा : प्रियंका गांधी

मैसुरू, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में आह्वान किया कि वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएं ताकि उनके हित में काम हो सके।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक हालिया टिप्पणी को लेकर मंगलवार को सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कर्नाटक को मौजूदा समय के किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और वोट नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलने की धमकी देना राज्य की जनता का अपमान है।

उन्होंने यहां एक चुनावी सभा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि इस 40 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार ने कर्नाटक को बेशर्मी एवं बेरहमी से लूटा है।

प्रियंका गांधी ने लोगों का आह्वान किया कि वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएं ताकि उनके हित में काम हो सके।

कांग्रेस महासचिव ने नड्डा का नाम लिए बगैर कहा, आज भाजपा के नेता धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो मोदी जी का अशीर्वाद नहीं मिलेगा। जिस जनता को बासवन्ना जी और नारायण गुरू जी ने अपना आशीर्वाद दिया हो, उसे आज के किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है।

उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणी जनता का अपमान है।

कांग्रेस ने पिछले दिनों ट्विटर पर नड्डा का एक वीडियो साझा किया था उसमें उन्हें यह बोलते सुना जा सकता है, कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे इसलिए मैं कमल के निशान पर वोट मांगने आया हूं। कर्नाटक में विकास जारी रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कहीं कर्नाटक वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है।

प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष के नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। यह कैसी बात है? इस देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री की सेहत अच्छी रहे और उनकी लंबी उम्र हो।

उनका कहना था, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह चुनावी मुद्दा है? वह बेरोजगारी, महंगाई की बात क्यों नहीं करते, आप लोगों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? यह चुनाव किसी भी नेता के बारे में नहीं है। यह चुनाव कर्नाटक के बारे में हैं, आपके अपने अभिमान के बारे में है।

प्रियंका गांधी ने लोगों का आह्वान किया, लूटने वाली सरकार को हटा दीजिए और ऐसी सरकार लाइए जो कर्नाटक के हित में काम करे।

उन्होंने कहा, पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस और जनता दल (एस) की सरकार चुनी थी। भाजपा ने तोड़फोड़ करके उस सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार बना ली। भाजपा की सरकार शुरू से ही एक धोखा थी। भाजपा की सरकार लालच के आधार पर बनी तो लालच के आधार पर ही निर्णय लेती रही। इसका नतीजा यह रहा है कि जो काम करने चाहिए थे, वो नहीं किए गए।

प्रियंका गांधी ने दावा किया, आपको दुर्बल नेता मिले, बार-बार मुख्यमंत्री बदला गया, मंत्रिमंडल

का विस्तार नहीं हुआ, शासन की सारी चीजें ढीली पड़ गई हैं...सबसे दुखद की बात है कि 40 प्रतिशत की कमीशन वाली सरकार ने आपको बेशर्मी और बेहरमी से लूटा। कहा जाता है कि कर्नाटक प्रदेश से 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि भर्तियों में घोटाला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ऐसा करने वालों का संबंध भाजपा से था।

कांग्रेस महासचिव ने अपनी पार्टी के चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए कहा, हम वादे नहीं आपको गारंटी दे रहे हैं।

कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी।

पंजाब में किसी की 'साजिश' से हो रहीं 'भड़काऊ घटनाएं' : सुखबीर बादल

चंडीगढ़, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मंगलवार को कहा कि पंजाब में हाल के महीनों में सिलसिलेवार भड़काऊ घटनाएं हो रही हैं, विशेष रूप से जालंधर उपचुनाव की घोषणा के बाद से। इसके पीछे एक गहरी साजिश है।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के एक न्यायाधीश इसकी जांच कराने की मांग की। बादल ने कहा कि पंजाबी चाहते हैं कि इस साजिश के पीछे के शातिर मास्टरमाइंड का पदार्फाश हो और उसे सजा मिले। उन्होंने कहा, पंजाबियों को यह जानने का अधिकार है कि इन साजिशों को अंजाम देने वालों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है।

यहां एक बयान में अकाली दल प्रमुख ने कहा कि संवेदनशील घटनाओं को लेकर जताए जा रहे संदेहों पर केंद्र और पंजाब, दोनों सरकारों को सफाई देनी चाहिए।

बादल ने कहा, 'लोगों को संदेह है कि जालंधर और देश के बाकी हिस्सों में सस्ते चुनावी लाभ के लिए पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को अस्थिर करने की नीयत से किसी का अंडरकवर ऑपरेशन काम कर रहा है।'

बादल ने कहा, राज्य और केंद्र सरकारों को विश्वसनीय और तथ्य-आधारित सबूतों के साथ इन संदेहों को दूर करना चाहिए।

अकाली दल प्रमुख ने कहा, आप सरकार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और विकास सुनिश्चित करने और शासन करने में अपनी घोर विफलता से ध्यान हटाने के लिए बार-बार नाटक कर रही है। हर बार इसे अपने वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को शर्मनाक आरोपों का सामना करना पड़ता है। इनका देह व्यापार में लिप्त होना या भारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना शर्मनाक है।

बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब में फिर से आग लगाने की खतरनाक साजिश पर काम होता दिख रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'हमें यह जानने की जरूरत है कि इन सबके पीछे कुटिल मास्टरमाइंड कौन है।'

अमृतपाल से आईबी अधिकारियों ने डिब्रूगढ़ जेल में पूछताछ की

गुवाहाटी, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह से मंगलवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारियों ने पूछताछ की। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वारिस पंजाब दे (डब्ल्यूपीडी) प्रमुख को अलग सेल में रखा गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक, उन्हें अपने करीबी सहयोगी पापलप्रीत सिंह सहित संगठन के अन्य सदस्यों से मिलने की इजाजत नहीं थी।

रविवार को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल लाए जाने से पहले अमृतपाल के नौ सहयोगी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद थे।

डिब्रूगढ़ जेल के एक सूत्र ने खुलासा किया कि आईबी अधिकारी आज सुबह जेल के अंदर गए और वारिस पंजाब दे प्रमुख से पूछताछ की।

असम पुलिस इस मामले में चुखपी साधे हुए है।

असम पुलिस के महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार भुइयां ने आईएएनएस को बताया, 'आईबी और रॉ सहित सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी राज्य में तैनात हैं। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि किसी कैदी से पूछताछ करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी से किसी को आना पड़े।' हालांकि, उन्होंने अमृतपाल से पूछताछ पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी अधिनियम) के प्रभावी और सख्त कार्यान्वयन के लिए कई दिशा-निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के लिए निर्देश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा जारी किए गए, जिन्होंने कहा कि लिंग-निर्धारण के आधार पर भ्रूण का गर्भपात लैंगिक असमानता को जारी रखने का एक शक्तिशाली साधन है।

लिंग-निर्धारण आधारित गर्भपात लैंगिक असमानताओं को बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। भ्रूण की यौन जानकारी तक पहुंच का प्रतिबंध सीधे तौर पर स्त्री-द्वेष की समस्या से संबंधित है, जो न केवल इस देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रभावित करता है। लिंग या लिंग के ज्ञान को नियंत्रित करने का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चे की रक्षा करना है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम लिंग-निर्धारण परीक्षणों का डर पैदा करने में आंशिक रूप से सफल रहा है, लेकिन इसने अभी तक कन्या भ्रूण के लिए एक सुरक्षित गर्भ की आवश्यकता को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है, जो एक अन्य मुद्दा था जिसे संबोधित करने का प्रयास किया गया था।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, इस अधिनियम के तहत अपराध, जिन पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव है, दोहरी हिंसा को जन्म देते हैं यानी अजन्मी बच्ची के खिलाफ और मां के खिलाफ उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर करके स्वास्थ्य को खतरे में डालना। कहने की जरूरत नहीं है, एक महिला होगी जब उसके गर्भ में एक लड़की होती है तो उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है, केवल तभी जब एक अवैध लिंग-निर्धारण परीक्षण किया जाता है।

इसलिए, पीसीपीएनडीटी अधिनियम और नियमों को जिला उपयुक्त अधिकारियों, जांच अधिकारियों और अभियोजकों को अधिनियम की धारा 28 के विशिष्ट अनिवार्य प्रावधानों और पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में सूचित करने के लिए अवगत कराया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत शिकायत की जाती है।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में स्पष्ट हैं ताकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के शासनादेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और अधिकारियों के अधिकारियों के बीच संचार में सुधार हो सके।

न्यायाधीश ने कहा, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

अदालत ने आगे कहा कि ऐसी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, स्थान और तंत्र के बारे में जनता को सूचित करने के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और वेबसाइटों का निर्माण करना उचित होगा।

उपयुक्त प्राधिकरण का गठन, उनके संपर्क विवरण, ई-मेल आईडी और फोन नंबर सहित, जहां शिकायत की जा सकती है, सभी अस्पतालों और क्लीनिकों में विशिष्ट विशिष्ट स्थानों पर भी उल्लेख किया जा सकता है, जहां अल्ट्रासोनोग्राफी या अन्य पूर्व-प्रसव संबंधी नैदानिक तकनीकें उपलब्ध हैं या की जा रही हैं, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित समझा जाने वाला कोई अन्य स्थान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आम व्यक्ति को अनुचित तरीके से शिकायत दर्ज करने के लिए गुमराह नहीं किया जाता है। प्राधिकरण शिकायत पर

कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सक्षम नहीं है।

अदालत ने अपनी टिप्पणियों और निदेशों को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालयों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और निदेशक (अकादमिक), दिल्ली न्यायिक अकादमी के समक्ष रखने का आदेश दिया।

एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के कदम उठाए जाएं और तीन महीने के भीतर अनुपालन दर्ज किया जाए। न्यायमूर्ति शर्मा ने निर्देश जारी किए क्योंकि उन्होंने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत मनोज कृष्ण आहूजा नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने, हालांकि, अधिनियम की धारा 28 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दायर किसी भी शिकायत के अभाव में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया। यह माना गया कि वही कानून में खराब था।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR GODAVARI TUESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:4 DrawDate on:25/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 37E 40140
Cons. Prize ₹1000/- 40140 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
12930 37305 54370 67753 76853 80517 82648 93962 94397 98007
3rd Prize ₹450/-
0888 4647 5690 6069 6144 6206 7477 7791 8626 9745
4th Prize ₹250/-
1937 1998 3653 4342 7488 8035 8073 8617 8818 8867
5th Prize ₹120/-
0031 0056 0160 0208 0240 0243 0746 1212 1311 1389
1595 1628 1680 1774 1861 1919 2102 2253 2322 2395
2466 2492 2571 2672 2751 2852 2924 3093 3145 3173
3311 3373 3378 3488 3570 3781 3802 3823 3860 3876
4033 4138 4158 4227 4320 4624 4745 4773 4979 5496
5549 5600 5646 5706 5756 5809 5888 6034 6241 6299
6376 6468 6624 6680 6826 6882 7002 7045 7123 7128
7235 7247 7315 7332 7491 7708 7781 7939 8021 8110
8195 8415 8558 8648 8854 8942 9000 9042 9043 9208
9272 9297 9437 9646 9672 9683 9690 9698 9725 9862
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR WAVE TUESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:4 DrawDate on:25/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 84J 66542
Cons. Prize ₹1000/- 66542 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
05183 11170 18142 50249 58066 58562 73130 79440 84351 92226
3rd Prize ₹450/-
2915 3076 3547 4359 5279 5459 5724 5797 8076 8957
4th Prize ₹250/-
0163 1338 1828 4927 5013 5033 5164 5609 6829 7777
5th Prize ₹120/-
0331 0337 0521 0589 0618 0698 0765 0778 0861 0910
1017 1130 1374 1425 1430 1552 1717 1987 1988 1996
2161 2209 2212 2313 2385 2458 2545 2606 2780 2808
2872 2935 2986 2992 3011 3081 3115 3229 3343 3348
3949 4189 4290 4302 4353 4538 4576 4706 4768 4833
4903 4925 4978 5007 5031 5040 5048 5360 5416 5670
5763 5859 5920 6026 6168 6206 6468 6537 6597 6774
6868 6904 7076 7134 7188 7202 7246 7272 7426 7492
7494 7596 7641 7693 7827 7872 8311 8450 8778 9117
9178 9191 9386 9409 9504 9546 9576 9711 9713 9833
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR GOOSE TUESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:4 DrawDate on:25/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 95B 17027
Cons. Prize ₹1000/- 17027 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
08111 08872 14040 30424 44732 54535 84495 87311 97302 97437
3rd Prize ₹450/-
1039 1388 2083 3056 3208 4340 4541 5018 7820 8577
4th Prize ₹250/-
0744 1439 2180 2716 3355 3557 5624 7224 7518 9582
5th Prize ₹120/-
0076 0320 0338 0486 0820 0838 0972 1186 1251 1329
1399 1433 1945 2004 2115 2158 2331 2374 2387 2510
2603 2713 2940 3190 3313 3319 3432 3493 3651 3668
3741 3843 3964 4042 4057 4129 4293 4296 4304 4366
4469 4472 4621 4637 4796 4922 4929 4975 5003 5012
5030 5076 5173 5196 5199 5313 5405 5431 5695 6219
6260 6261 6272 6337 6657 6764 6766 7056 7147 7298
7331 7622 7873 7879 7972 8080 8155 8270 8284 8381
8449 8961 9057 9141 9142 9441 9475 9503 9527 9547
9570 9590 9621 9731 9821 9875 9932 9947 9955 9982
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

सच सामने आए

देश के टॉप मेडल विनर पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर बैठ गए हैं। रविवार रात उन्होंने वहीं बिताई और उनका कहना है कि जब तक उनकी शिकायत पर उपयुक्त कार्रवाई नहीं होती वह धरने पर बैठे रहेंगे। यह स्थिति वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है।22 खासकर इसलिए कि पहलवानों ने कोई पहली बार अपनी मांग नहीं रखी है। तीन महीने पहले भी वे धरने पर बैठे थे। उनकी शिकायत भी कोई मामूली नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष के खिलाफ यौनशोषण का आरोप ऐसा नहीं हो सकता, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए।

हैरत की बात यह है कि तब इन पहलवानों को पूरे मामले की जांच-पड़ताल के बाद मुनासिब कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था, वह किसी अंजाम तक पहुंचता नहीं दिख रहा। हालांकि जानी-मानी बॉक्सर मैरी कोम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। कहा जा रहा है कि उस समिति ने इसी महीने के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी, लेकिन उस बारे में कोई औपचारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। अगर सचमुच यह रिपोर्ट आ गई है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? चूंकि इस मामले में आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाए गए हैं, इसलिए गोपनीयता बरतने का कोई मतलब नहीं बनता। देशवासियों के सामने उन पहलवानों और महिला पहलवानों ने आकर शिकायत की, जो देश का गौरव हैं।

चाहे कुश्ती महासंघ हो या खेल मंत्रालय, वे समय पर इनकी शिकायत सुनने और उनका हल निकालने में नाकाम रहे। तभी ये पहलवान जंतर-मंतर पर धरना देने को विवश हुए। इसलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर इन पहलवानों की शिकायत गलत पाई गई तो वह बात भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। लेकिन अगर उनकी शिकायत सही है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ बिना देर किए कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि ऐसा होता नहीं दिख रहा, इसलिए खेल मंत्रालय समेत देश का पूरा खेल ढांचा संदेह के घेरे में आ रहा है। और, अब तो एक नाबालिग समेत सात महिला पहलवानों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी है।

हालांकि शिकायत मिल जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और इसके लिए भी पहलवानों को अदालत का रुख करना पड़ा। समझना चाहिए कि यह किसी खेल संगठन या उसके पदाधिकारियों से ही जुड़ा मसला नहीं है। इससे यह सवाल भी जुड़ा है कि हम खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? उनकी शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं? दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को इंसाफ पाने के लिए बार-बार ऐसे सड़क पर उतरना पड़े, यह सरकार और प्रशासन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है।

झूठे नैरेटिव का सच से सामना

हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय मंत्री

प्रमुख नैरेटिव को अक्सर एक वस्तुपरक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे नैरेटिव अक्सर उन लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका अपना एक एजेंडा होता है और इसलिए उन्हें एक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। ईएच कार की प्रसिद्ध उक्ति है, 'इतिहासकार अपने तथ्यों के बिना जड़हीन और निरर्थक है; इतिहासकार के बिना तथ्य मृत और अर्थहीन हैं।

इसका एक उदाहरण है - ईंधन की कीमतों का संदर्भ और इससे जुड़ी समझ। पेट्रोल और डीजल की लगातार कम कीमतें, जो संभव नहीं हैं, केवल कल्पना की दुनिया के लिए हो सकतीं हैं।

भारत में ईंधन की कीमतें बहुत अधिक हैं, यह एक ऐसे नैरेटिव पर आधारित है, जो बहुत ही दोषपूर्ण है। वास्तव में, ये कीमतें, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऊर्जा उपलब्धता और इसे किफायती बनाए रखने के प्रयासों के कारण, दुनिया की सबसे कम कीमतों में से एक हैं।

पीएम मोदी ने मई 2022 और नवंबर 2021 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार कटौती की थी जिनसे पेट्रोल में 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 15 रुपये प्रति लीटर की कमी आयी। इनसे केंद्रीय खजाने पर सालाना 2.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अलावा, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, निर्यातकों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए घरेलू उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात उपकर और विंडफॉल (अप्रत्याशित) टैक्स भी लगाया। तेल विपणन कंपनियों ने (ओएमसी) 'अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक' होने का परिचय देते हुए, भारतीय नागरिकों को नियंत्रित दरों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की, जिसके कारण इन्हें ऊंची कीमतों के दौर में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा इन कीमतों को 6 अप्रैल 2022 से अपरिवर्तित रखा गया है।

कई राज्य सरकारें ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए वैट में कटौती की। यहां कई बातें महत्वपूर्ण हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ राज्य वैट दरों में कटौती नहीं करने और राज्य में कीमतों को कम नहीं करने के अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहे।

गौरतलब है कि बीजेपी शासित राज्यों और जिन राज्यों ने अपनी वैट दरों में कटौती की है, वहां पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर आम तौर पर 14.50 रुपये से 17.50 रुपये प्रति लीटर है, जबकि राज्यों में वैट की सीमा 26 रुपये से 32 रुपये प्रति लीटर है। इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है और खर्च में भारी अंतर आता है।

कांग्रेस शासित राजस्थान में उपभोक्ता, पेट्रोल के लिए 108.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 93.80 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं, जो पड़ोसी बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश की तुलना में पेट्रोल पर लगभग 12 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 4 रुपये प्रति लीटर अधिक है, जहां उपभोक्ता क्रमश: 96.57 रुपये प्रति लीटर और 89.76 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करते हैं।

यूपीए सरकार द्वारा 2005-12 के बीच किए गए स्थायी नुकसान के कारण, जिसके तहत ओएमसी को अंडर-रिकवरी के बजाय 1.44 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक तेल बांड जारी किए गए थे, भारतीय करदाता अभी भी ब्याज + मूलधन के रूप में 3.2 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं।

वाईएसआर-कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश: 110.48 रुपये प्रति लीटर और 98.27 रुपये प्रति लीटर है, जो कर्नाटक की तुलना में लगभग 10 रुपये अधिक है, जहां यह क्रमश: 101.94 रुपये प्रति लीटर और रु. 87.89 रुपये प्रति लीटर है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे साल भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत वाले राज्य का रिकॉर्ड बनाया है।

टीआरएस शासित तेलंगाना में, उपभोक्ता भारत में पेट्रोल की दूसरी उच्चतम दर @ 109.66 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करते हैं। यह यूपी (96.57 रुपये प्रतिलीटर) की तुलना में 13 रुपये प्रति लीटर अधिक है। प्रतिशत में, तेलंगाना में पेट्रोल पर वैट की दर 35.2 प्रतिशत है, जबकि यूपी में यह 26.8 प्रतिशत है! यूपी के 17.48 प्रतिशत की तुलना में तेलंगाना में डीजल पर वैट की दर 27 प्रतिशत है!

पश्चिम बंगाल में, उपभोक्ता पेट्रोल के लिए 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 92.76 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करते हैं, जबकि असम में उपभोक्ता क्रमश: 97.02 रुपये प्रति लीटर और 88.30 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करते हैं। यदि दीदी को अपने लोगों की परवाह है, तो वे पेट्रोल के दाम, 100 रुपये प्रति लीटर से कम क्यों नहीं कर देतीं हैं?

पाखंड साफ़, स्पष्ट और बिना ठोस आधार के हैं, जिसे सभी देख सकते हैं। यहां तक कि जब विमान ईंधन की कीमतों की बात आती है, जो आतिथ्य और यात्रा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ राज्यों का घोर लालच स्पष्ट और साफ़ दिखाई पड़ता है। हाल के महाराष्ट्र बजट 2023 में: राज्य सरकार ने जेट ईंधन पर वैट को 18 प्रतिशत तक घटा दिया है, जबकि भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र - दिल्ली - उन राज्यों में से एक है, जो अभी भी जेट ईंधन पर 25 प्रतिशत तक का ऊंचा टैक्स लगाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय गैस सूचकांकों (जापान कोरिया) में जनवरी 2021 और फरवरी 2023 के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों में 228 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, भारत में (सीएनजी) मूल्य वृद्धि (दिल्ली प्रतिनिधि बाजार) लगभग 83 प्रतिशत तक सीमित थी। ऐसा 2013-14 के आवंटन से घरेलू गैस आवंटन में लगभग 250 प्रतिशत तक की वृद्धि करने और सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू गैस को अन्य गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से अलग करने जैसे कदमों के कारण संभव हुआ।

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पद्धति को संशोधित करने का एक बड़ा निर्णय लिया है, जो भारत के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह संतुलित निर्णय, भारतीय प्राकृतिक गैस की कीमत को भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत की तुलना में 10 प्रतिशत पर निर्धारित करता है। उद्योग के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा संतुलित सुधार के रूप में इस निर्णय की सराहना की जा रही है। उद्योग जगत अधिक गतिशील और मजबूत मूल्य निर्धारण व्यवस्था से लाभान्वित होता है, उपभोक्ता पहले से ही इनका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि घरेलू पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में 7-8 रुपये तक की कटौती की गयी है।

हालांकि, इस संकटपूर्ण समय में अपने 1.4 बिलियन नागरिकों को सुलभ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने में भारत की अभूतपूर्व सफलता को पूरी दुनिया स्वीकार करती है, लेकिन कुछ पाखंडी राज्य सरकारें और राजनीतिक नेता अपनी नागरिक-विरोधी रणनीति को छिपाते हुए अर्थहीन बातें बोलते रहते हैं। यह उनके लिए ईंधन पर राज्यों के टैक्स में कटौती करने का समय है।

आसान नहीं भारत की राह

सतीश सिंह

बाघ अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग आमतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। ए

शियाई बाघ अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि शामिल हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में विकास का आधार निर्यात होता है। अर्थात ऐसे देश निर्यात की मदद से विकास की रफ्तार को कायम रखते हैं। सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि देशों ने निर्यात और मुक्त व्यापार की नीतियाँ अपनाई और विकास के प्रवाह को कायम रखने में सफल रहे।

भारत भले ही इंग्लैंड को पछाड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था उससे बड़ी है, लेकिन भारत के विकास के पीछे निर्यात न होकर दूसरे कारक हैं। भारत में निर्यात की रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है, लेकिन इसे अपेक्षित कतई नहीं कहा जा सकता है। भारतीय बाजार को कारोबार हेतु दुनिया के लिए अभी भी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। देश में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी कम है। भारत जब आजाद हुआ था, तब भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.7 लाख करोड़ रुपये की थी, जो वित्त वर्ष 2020-21में बढ़कर 135.13 लाख करोड़ रुपये की हो गई।

वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह बहुत सफल नहीं रही। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं का भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सका। हालांकि, वर्ष 1961 से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दृष्टिगोचर होने लगा। वर्ष 1950 से वर्ष 1979 तक देश की जीडीपी औसतन 3.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही थी, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर कहा गया, जबकि वर्ष 1950 से वर्ष 2020 तक भारत की जीडीपी वृद्धि दर औसतन 6.15 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी। वर्ष 2010 की पहली तिमाही में जीडीपी दर 11.40 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, कोरोना काल में आधार प्रभाव के कारण इससे भी बेहतर जीडीपी वृद्धि दर देखी गई, जबकि वर्ष 1979 की चौथी तिमाही में इसने 5.20 की सबसे कम वृद्धि दर्ज की। उल्लेखनीय है कि महामारी में जीडीपी वृद्धि दर माइनस में चली गई थी। वर्ष 1960 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 81.3 अमेरिकी डॉलर थी, जो अप्रैल 2021 में बढ़कर 7332.9 अमेरिकी डॉलर हो गई। देश में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 1980-81 से वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान औसतन 3.1 प्रतिशत रही, जो वित्त वर्ष 1992-93 से वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान बढ़कर औसतन 3.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो पुन: वित्त वर्ष 2003-2004 से वित्त वर्ष 2007-2008 के दौरान दोगुनी होकर औसतन 7.2 प्रति वर्ष के स्तर पर पहुंच गई। बाद के वर्षों में भी इसमें उतरोत्तर तेजी देखी गई।

वित्त वर्ष 2021-22 की दिसम्बर तिमाही के दौरान जीडीपी 5.4 प्रतिशत रही और तीसरी और चौथी तिमाही में भी जीडीपी वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, लेकिन समग्र रूप से वित्त वर्ष 2021 के दौरान जीडीपी में 8.7 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2021की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2022की पहली तिमाही के दौरान भी जीपीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई। जीडीपी में कमी के कारक महामारी, भू-राजनैतिक संकट, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, महंगाई की ऊंची दर आदि रहे। वर्ष 1991 में विदेश व्यापार, कर सुधार, विदेशी निवेश आदि क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिली। वर्ष 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गई और विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी बढ़कर 3.1 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। देश में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ, लेकिन अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है अर्थात देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में निजी क्षेत्र अभी भी बहुत पीछे है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 9 भारतीय निजी और सरकारी बैंकों की रेटिंग का उन्नयन करते हुए उसे आउटलुक निगेटिव से स्टेबल कर दिया गया है। मूडीज ने जिन बैंकों की रेटिंग का उन्नयन किया है, उनमें निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। मूडीज ने बैंकों के अलावा भारत की रेटिंग का भी उन्नयन करते हुए सॉवरेन निगेटिव से स्टेबल कर दिया है। भारत की रेटिंग फिलवक्त बीएए3 है। मूडीज द्वारा भारत और भारतीय बैंकों की रेटिंग उन्नयन का अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बैंकों से जुड़े जोखिम में कमी आ रही है। आज दुनिया के विकसित देश मंदी की गिरफ्त में आने के कगार पर हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मंदी के प्रमुख कारकों, जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई आदि के मामलों में भारत दुनिया के विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है।

फिलवक्त, भारत के तमाम पड़ोसी देशों सहित यूरोप और अमेरिका में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत में महंगाई मार्च 2023 में घटकर 15 महीनों के निचले स्तर 5.66 प्रतिशत पर पहुंच गई। इधर, यूरोपीय देशों की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई हैं, लेकिन रुपये की स्थिति उनके मुकाबले बेहतर है और हाल में रुपये की तुलना में डॉलर में कमजोरी देखी गई है। पड़ताल से साफ है, बाघ अर्थव्यवस्था के प्रमुख मानक निर्यात के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है, जिसके कारण मौजूदा विकास दर कम है। ऐसे में जब तक भारत मेक इन इंडिया की संकल्पना को पूरी तरह से साकार करने में सफल नहीं होता है, भारत का बाघ अर्थव्यवस्था बनने का सपना साकार नहीं हो सकता है। जब भारत सभी वस्तुओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब उसे स्वत: आयात से मुक्ति मिल जाएगी।

आबादी के शिखर पर पहुंचकर याद आते हैं बाबा साहेब

श्यौराज सिंह बेचैन

हाल ही में जारी हुई स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, भारत दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चिंताजनक बात यह है कि भारत में जिन समुदायों में गरीबी अधिक है, स्त्री शिक्षा का स्तर नीचे है, जीवन शैली में अतार्किकता और अवैज्ञानिकता अधिक है, वहां आबादी का ग्राफ ऊपर है। ग्रामीण भारत में आज भी बाल-विवाह प्रचलित है। विवाह की वास्तविक आयु से पहले ही बच्चियां मां बन जाती हैं। हालांकि देश में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ी है, जिससे मृत्यु दर कम हुई है और आबादी बढ़ी है। हमारे यहां कोरोना के चरम दौर में भी मृत्यु दर चीन की अपेक्षा कम रही है। लेकिन जीवन की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। जनसंख्या का नया आंकड़ा आने के बाद दंभी चीन कह ही रहा है कि हम आबादी में पीछे जरूर हुए हैं, लेकिन नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में आगे हैं।

आजादी के पहले हमारे राष्ट्र-निर्माताओं, चिंतकों और योजनाकारों ने क्या जनसंख्या को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की थी? नए भारत के निर्माण के संदर्भ में जनसंख्या नीति को लेकर राष्ट्रीय नेताओं की चिंताएं और योजनाएं क्या थीं? सवाल यह भी कि आबादी से संविधान निर्माता आंबेडकर का क्या संबंध है। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लार्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। बाद में अर्थशास्त्र के शोधार्थी के रूप में भीमराव आंबेडकर ने उस जनगणना का विश्लेषण किया था। लेकिन वह संविधान में इस बारे में तत्काल कुछ अधिक जोड़ नहीं पाए थे। 'कुटंब नियोजन अवश्य होना चाहिए', यह विचार भारतीय नेताओं में सर्वप्रथम और सार्वजनिक तौर पर डॉ. आंबेडकर ने व्यक्त किया था। वह 'संतति नियमन यानी परिवार नियोजन' विषयक प्रस्ताव लेकर बंबई विधानसभा में जाने वाले थे, परंतु उस समय वह इतने अस्वस्थ हो गए थे कि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सख्त हिदायत दी थी। तो वह प्रस्ताव उन्होंने श्री पीजे रोहन की मार्फत 10 जनवरी, 1938 को बंबई विधानसभा में पेश किया। उनका सुझाव था कि सरकारों को परिवार नियोजन का जोरदार प्रचार करना चाहिए तथा आम नागरिकों को संतति रोधक साधन सहज सुलभ कराने चाहिए।

डॉ. आंबेडकर ने जनसंख्या संतुलन का मुद्दा तब उठाया था, जब भारत की आबादी मात्र 30 करोड़ थी। वह आशावादी थे, परंतु जानते थे कि जिन सामाजिक समुदायों में अशिक्षा और गरीबी अधिक होगी, वहां आबादी भी अधिक होगी। आर्थिक-सामाजिक मुद्दों के गहरे जानकार आंबेडकर जनसंख्या संतुलन के लिए दूरगामी योजना बनाना चाहते थे। वह कार्य करने का अवसर तो उन्हें नहीं दिया गया, पर उनके सुझावों का असर सरकारी योजनाओं पर कमोबेश रहा। उनकी कुटुंब नियोजन की प्रस्तावना के अनुसार, उनके जीवन काल यानी 1952 में ही परिवार नियोजन को राजकीय कार्यक्रमों का हिस्सा बनना पड़ा, अपितु उनके परिनिर्वाण के दो दशक बाद 1976 में 42 वां संविधान संशोधन कर सूची में 'जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्य' जोड़ा गया।

अपने यहां हमेशा ही जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर बात होती रही है। वर्ष 1968 में पदोन्नति के लिए 'हम दो, हमारे दो की सीमा रेखा तय की गई थी। परंतु उसका पालन नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण सहित 20 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन इतने अव्यावहारिक और अतिवादी गति से किया था कि जबरन नसबंदी आपातकाल के बाद हुए चुनाव में उनकी हार की बड़ी वजह बनी। नरसिंह राव सरकार ने वर्ष 1992 में सांसदों, विधायकों के लिए दो बच्चों की नीति की बात की थी। परंतु उस पर अमल न हो सका। उत्तर प्रदेश में लोक-सेवकों को एक बच्चा रखने का फैसला भी बदल दिया गया था।

आजाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तब देश की जितनी आबादी (36 करोड़) थी, उतनी आज अनुसूचित जाति/जनजाति की हो चुकी है। यह बात किसी की भी समझ में आती है कि बच्चे अधिक होने से ज्यादा जरूरी है कि वे स्वस्थ, सक्रिय और सफल हों। जनसंख्या घनत्व राष्ट्र के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी करता है। जैसे, नागरिकों के आयु-काल की उपयोगिता, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षित वृद्धि हो पाना, इलाज और दवाएं सर्वसुलभ होना, भूख की समस्या का पूरी तरह हल होना, रोजगारपरक शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशी एकरूपता में वृद्धि होना आदि-आदि।

जन्म दर बढ़ती है, तो उसी अनुपात में लोगों के विकास के अवसर भी बढ़ाने अपेक्षित हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो अवांछित आबादी का विस्फोट एक प्रकार की आपदा है। जन्म के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले लोग जनसंख्या घनत्व को समस्या ही नहीं मानते हैं। जाति आधारित मत समीकरण बनाने वाले केवल स्व-जाति संख्या में वृद्धि होते देखना चाहते हैं। इन दिनों कई राज्यों में जाति जनगणना की मांग जोरों पर है। देर-सबेर जातिवार जनगणना यदि होती है, तो वह नए आंकड़े लेकर आएगी। तब यह भी पता चलेगा कि किन जातियों में जन्म दर अधिक है और किन जातियों में कम है।

कभी डॉ. आंबेडकर को आबादी से संबंधित उनके वैज्ञानिक विचार के लिए दुस्साहसी ही कहा गया था। आज भी बहुसंख्य भारतीय जनसंख्या असंतुलन को लेकर अपेक्षित फिक्रमंद नहीं हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम अमृतोत्सव मना रहे हैं। उत्सव की यह खुशी और स्थायी होगी, यदि हम जनसंख्या घनत्व के दबाव से आजाद होने को संकल्पबद्ध हों।

कार्डियोलॉजिस्ट बनकर रखें लोगों के दिलों का ख्याल

एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के पास ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान में संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोगियों की सेवा करने, दूसरों के प्रति दया करने, आत्म-प्रेरित होने और चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी है कि आप इसका पूरी तरह ख्याल रखें।

आमतौर पर लोग अपने दिल का ख्याल रखने के लिए खानपान से लेकर अन्य कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। कार्डियोलॉजी चिकित्सा का एक प्रभाग है जो हृदय विकारों से संबंधित निदान और उपचार से संबंधित है। दिल के विकारों से निपटने वाले चिकित्सा चिकित्सकों को आमतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की इस शाखा का बेहद महत्व है और अगर आप चाहें तो इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं-

क्या होता है काम

एक हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय, धमनियों और नसों का डॉक्टर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की विफलता, जन्मजात हृदय दोष और कोरोनरी धमनी रोग का निदान और उपचार प्रदान करते हैं। इसमें धमनियों के संकीर्ण होने, हृदय के वाल्व में समस्याएं, मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान और पेरिकार्डियम के विकार के कारण प्रतिबंधित परिसंचरण के कारण होने वाली समस्याएं शामिल हैं।

स्किल्स

एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के पास ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान में संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोगियों की सेवा करने, दूसरों के प्रति दया करने, आत्म-प्रेरित होने और चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए अनुशासन, धैर्य, उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास का होना भी उतना ही आवश्यक है। उनके पास जीवन की खतरनाक स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कैरियर कोच कहते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ को भी आहार और व्यायाम विशेषज्ञ भी होना चाहिए।

योग्यता

एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री के अलावा कई सालों की प्रैक्टिस, लाइसेंस व बोर्ड सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एमडी/एमएस या डीएनबी की डिग्री लेने के बाद इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन के लिए डीएम इन कार्डियोलॉजी की डिग्री लेनी होगी। इस डिग्री की अवधि लगभग तीन साल की होती है।

अवसर

कॅरियर काउंसलर के अनुसार, एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में बतौर डॉक्टर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्डियक रिहैबिलेशन सेंटर या क्लीनिक टेस्टिंग सेंटर्स में भी काम कर सकते हैं। वहीं आप खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं और खुद का क्लीनिक खोल सकते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ाना पसंद करते हैं, वे मेडिकल कॉलेजों में बतौर लेक्चरर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

आमदनी

एक कार्डियोलॉजिस्ट की आमदनी उसके अनुभव व भौगोलिक स्थान पर मुख्य रूप से निर्धारित होती है। जो कार्डियोलॉजिस्ट शहर में काम करते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सैलरी मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी का स्तर कम हो सकता है। हालांकि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में बतौर फ्रेशर काम शुरू करते हैं, तब भी शुरूआती दौर में आप 25000 रूपए आसानी से कमा सकते हैं। जबकि निजी अस्पतालों में वेतन अधिक हो सकता है। वहीं कुछ वर्षों के अनुभव के बाद आपकी आमदनी लाखों में हो सकती है।

प्रमुख संस्थान

- गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली
- रविन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस, कोलकाता
- मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली
- आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे
- संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ

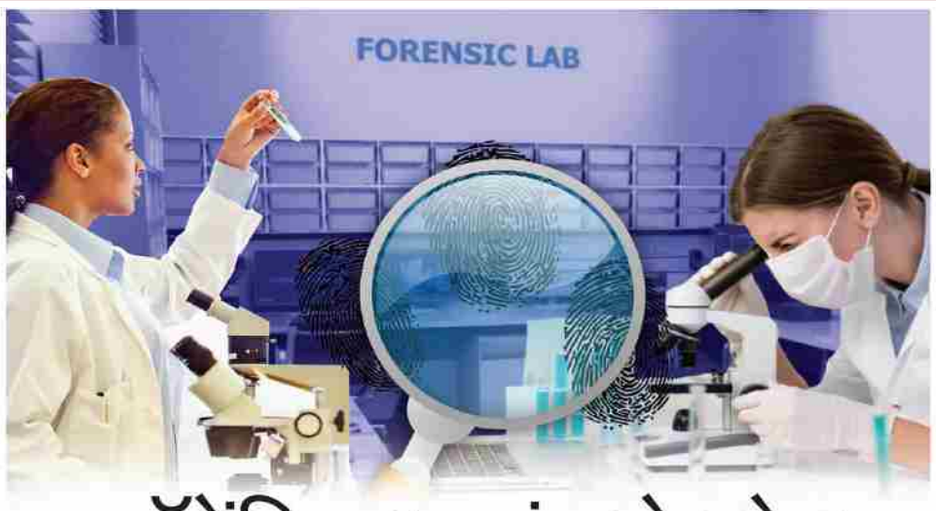

फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कॅरियर कैसे बनाएं? कोर्स, जॉब और सैलरी

फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम स्पॉट पर मौजूद सबूतों की जाँच करते हैं और अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए वे क्राइम सीन, ब्लड सेंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग आदि की जांच करते हैं।

फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल आपराधिक मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलोजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग आदि फील्ड्स शामिल होती हैं। इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम स्पॉट पर मौजूद सबूतों की जाँच करते हैं और अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए वे क्राइम सीन, ब्लड सेंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग आदि की जांच करते हैं।

कोर्स

फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने के लिए 12थ्द में साइंस होनी जरूरी है। आप फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ में एक वर्षीय डिप्लोमा कर सकते हैं। आप फॉरेंसिक साइंस 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी भी कर सकते हैं। इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन और रिसर्च करने के इच्छुक हों तो फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

एक फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को जिज्ञासु होना चाहिए और साहसिक कार्यों में दिलचस्पी होनी चाहिए। इस फील्ड में हर कदम पर चुनौती है इसलिए आपको दिमागी तौर पर मजबूत होना जरूर है। इसके साथ ही आपके अंदर मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी बेहद जरूरी है। एक फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को कई तरह की टेस्ट रिपोर्ट लिखनी होती हैं इसलिए आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए।फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को सबूतों की जाँच करनी होती है इसलिए आपको एकाग्रता और सतर्कता के साथ काम करना आना चाहिए।

कहां मिलेगी नौकरी

इस फील्ड में सरकारी और प्राइवेट जॉब्स की भरमार है। फॉरेंसिक साइंस में डिग्री हासिल करने के बाद आपको पुलिस, लीगल सिस्टम, इंवेस्टिगेटिव सर्विस जैसी जगहों पर जॉब मिल सकती है। वहीं, कोई प्राइवेट एजेंसी भी आपको बतौर फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स जॉब ऑफर कर सकती है। अगर आप में योग्यता है तो आपको फॉरेंसिक साइंटिस्ट इंटेलि?जेंस ब्यूरो और सीबीआई में भी नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप किसी फॉरेंसिक साइंस शिक्षण संस्थान में टीचर के रूप पढ़ा कर अच्छी सैलरी कमा सकते हैं।

सैलरी

योग्यता के आधार पर आपको शुरुआत में 20-50 हजार रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिल सकती है। समय के साथ अनुभव होने पर आप 6 से 8 लाख रुपये तक महीना कमा सकते हैं।

विदेशों में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

विदेशों से हायर एजुकेशन प्राप्त करना कई लोगों की टू-डू लिस्ट में शामिल होता है। कई लोग इसे प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग इसे प्राप्त करने से वंचित भी रह जाते हैं। विदेशों से हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने पर जीवन में कई अवसर मिलते हैं। हालांकि हायर एजुकेशन जितने बेहतर अवसर देता है उतना ही खर्चीला भी है। विदेशों में पढ़ाई करने के लिए एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता तो होते ही है साथ ही आवश्यकता होती है नॉलेज की। उसी नॉलेज और प्लानिंग में से एक है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो हमें कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त करने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है।

स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएं

हालांकि स्कॉलरशिप के लिए एकेडमिक स्ट्रेन्थ आवश्यक है। अगर मास्टर्स करने का आप प्लान बना रहे हैं तो आपका जीपीए 70 से अधिक है तो स्कोर बेहतर माना जाता है। लेकिन केवल इतना ही आवश्यक नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रोफाइल बेहद स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आप इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे स्पोर्टस, म्यूजिक, ड्रामा इत्यादि की डिटेल जरूर लिखें। इससे आपका प्रोफाइल बेहद स्ट्रांग बनेगा।

यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से आगे बढ़कर सोचें

ध्यान रखें कि विदेशों में पढ़ने के लिए केवल यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि कई संस्था स्कॉलरशिप प्रदान करती है। ये स्कॉलरशिप सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी दिया जाता है। अगर आप भारत में हैं तो कई संस्था जैसे टाटा आपको विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देगी। इसके साथ ही अगर आप विदेश में हैं तो वो देश भी विदेशों छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप प्लान पर कार्य करता है। इन स्कॉलरशिप के बारे में दोनें देशों के एजुकेशन डिपार्टमेंट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कोर्स से पहले कर दें अप्लाई

आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके शुरू होने से 18 महीने पहले आप अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन और वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगता है। ऐसे में आपको समय पर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और कोर्स में भी कोई समस्या नहीं होगी।

एप्लीकेशन का कराएं रिव्यू

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यह सबसे बेहतर आइडिया है कि उसका रिव्यू करा लिया जाए। रिव्यू कराने से एप्लीकेशन की कमियां सामने आएगी और उसके बाद सुधार किया जा सकेगा। अपना एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट लें और उसे किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएं। ये प्रोफेशनल आपके शिक्षक या कोई अन्य एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इससे आपको रिव्यू मिलेगा और आप एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे।

अधिक से अधिक रियल रहने का प्रयास करें

जब एप्लीकेशन लिखे तो ज्यादा से ज्यादा रियल रहने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी में आप खुद को निखारने और खुद को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं इसी कारण एप्लीकेशन में खुद को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर ना लिखें। जो हैं वह ईमानदारी के साथ लिखें और अपने स्किल, पैशन और इंटरेस्ट आदि के विषय में लिखें।

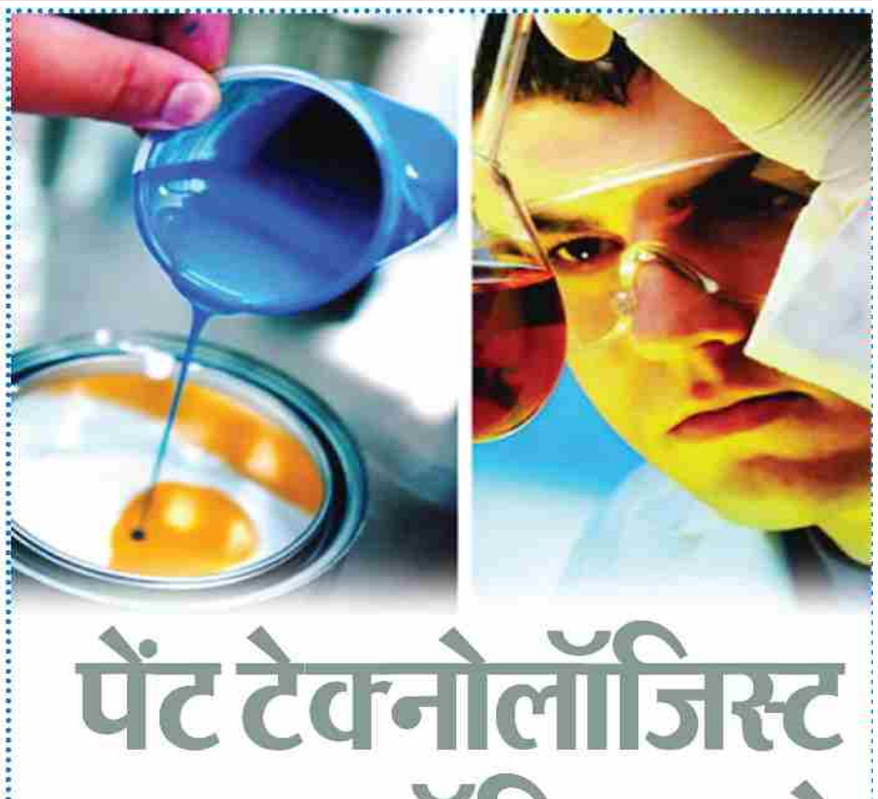

पेंट टेक्नोलॉजिस्ट बनकर कॅरियर को दें एक रंगीन दिशा

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पेंट की उपयुक्तता की पहचान और मूल्यांकन करता है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहकों को पेंट के सही उपयोग के बारे में समझाता है और उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करता है। रंगों का जीवन से एक गहरा नाता है। रंगों के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कपड़ों से लेकर घर तक हर जगह तरह-तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इन्हीं रंगों में अपना करियर बनाने की सोची है। अगर नहीं, तो अब आप इस क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। जी हां, पेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही क्षेत्र है। अगर आप भी चाहें तो इस क्षेत्र में अपना सफल भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में

क्या है पेंट टेक्नोलॉजी

पेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न इंग्रीडिएंट जैसे रॉल, पॉलिमर व पिगमेंट आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेंट टेक्नोलॉजी में, विभिन्न प्रकार के पेंट, उनके निर्माण, विभिन्न प्रकार के पेंट के उपयोग और पेंट के अनुप्रयोग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस विषय क्षेत्र में स्नातक करने वालों को पेंट टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है।

क्या होता है काम

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पेंट की उपयुक्तता की पहचान और मूल्यांकन करता है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहकों को पेंट के सही उपयोग के बारे में समझाता है और उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करता है। उनके काम में पेंट के नए रंग और बनावट विकसित करना, पेंट एप्लीकेशन के लिए नई तकनीक को विकसित करना आदि शामिल हैं। सरल भाषा में, वे नए उत्पादों को विकसित करने के साथ-साथ उन उत्पादों के गुणों को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए जिम्मेदार हैं जो पहले से ही विकसित किए गए हैं।

पर्सनल स्किल्स

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट को रंगों से बेहद प्यार होना चाहिए। साथ ही उसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी होने चाहिए, ताकि वह नए रंगों के साथ-साथ उनके टेक्टचर को भी बेहतर बना सके। एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट को मेहनती होना चाहिए। इसके अलावा, आपमें अच्छी संचार कौशल और टीम भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस उद्योग में अन्य पेशेवरों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही विभिन्न विभागों में टीमों का नेतृत्व करने के लिए पेंट टेक्नोलॉजिस्ट में प्रबंधकीय कौशल भी आवश्यक है।

योग्यता

इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको बीटेक इन पेंट टेक्नोलॉजी करना होगा। बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। अधिकाश संस्थानों द्वारा पेंट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को केमिकल इंजीनियरिंग में एक विषय के रूप में भी पेश किया जाता है।

संभावनाएं

पेंट उद्योग के विभिन्न विभागों में पेंट टेक्नोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। वे पेंट निर्माण कंपनियों के किसी भी विभाग में काम पा सकते हैं। पेंट उद्योग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट उद्योग पर निर्भर है। कई बड़ी-बड़ी पेंट मैन्युफैक्चिरिंग कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, शालीमार पेंट्स, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड आदि में पेंट टेक्नोलॉजिस्ट की हमेशा ही जरूरत होती है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, होम फर्निशिंग इंडस्ट्री आदि में भी कार्य कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में वेतन आपके अनुभव और उस सेक्टर पर निर्भर करता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में शुरुआत करने वाले व्यक्ति प्रारंभ में 1,25000 रूपए से 2,00000 रूपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है। वहीं, अनुभव बढ़ने के साथ-साथ आपका वेतन भी बढ़ता जाता है।

प्रमुख संस्थान

हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जलगांव, महाराष्ट्र
गार्वेयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॅरियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सांताक्रूज, महाराष्ट्र
लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर

नीतीश, राजद का अपना ठिकाना नहीं, ये पीएम क्या बनवाएंगे : प्रशांत किशोर

हाजीपुर, 25 अप्रैल (का.सं.)। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वकांक्षा पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार और राजद का अपना ठिकाना है नहीं, ये लोग क्या किसी को पीएम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश का हाल चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा।

बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुटे प्रशांत इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। अपनी जन सुराज पदयात्रा के 206 वें दिन मंगलवार को प्रशांत वैशाली के पातेपुर पहुंचे।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू भी इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद नायडू की सत्ता चली गई।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार का खुद का ठिकाना नहीं है, राजद का जीरो एमपी है वह देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का खुद का ठिकाना नहीं है वो देश की दूसरी पार्टियों को इकट्ठा कर रहा है।

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार है। क्या नीतीश कुमार और लालू उन्हे बिहार में एक भी सीट देंगे।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद के लड़के नहीं हों तो देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो उनकी काबिलियत पर उनको मिल जाएगी।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे 10 लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे और पहली ही केबिनेट में देंगे, अब आप बंगाल, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और अगस्त से सरकार में भी हैं।

प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी का जीवन निकल जाएगा 10 लाख नौकरियां देने में।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार के बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर लालू का साथ दिया, उसी तरह भाजपा ने बिहार के भविष्य को दांव पर लगाकर नीतीश का साथ दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को बिहार से सिर्फ 30-40 एमपी जीतने तक का ही मतलब है इससे ज्यादा उनके लिए बिहार कुछ भी नहीं है।

बाहुबली आनंद मोहन जेल से बाहर, नीतीश ने लगाए एक तीर से दो निशाने

हाजीपुर, 25 अप्रैल (का.सं.)। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के जेल से बाहर आने की सुचना से वहां की राजनीति गरमा गई है। उनकी रिहाई को लेकर कई नेताओं ने नितीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन भाजपा ने आनंद मोहन को लेकर अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार के भाजपा नेता खुलकर आनंद मोहन का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया?

दरअसल आनंद मोहन की रिहाई कराकर नितीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं।

आनंद मोहन बिरादरी से राजपूत हैं। बिहार में राजपूत जहाँ आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं वहीं राजनैतिक रूप से भी बहुत ज्यादा सक्रीय हैं। भले ही देश के किसी राज्य में जाति के आधार वोटिंग न करने की बात की जाती हो, लेकिन बिहार में आज भी जाति और धर्म के आधार पर खूब वोटिंग होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। सभी पार्टियां अपनी-अपनी राजनैतिक गोटियां बिछाने लगी हैं।

ऐसे में भला नीतीश कुमार कहां पीछे रहने वाले थे। नीतीश कुमार पर भले ही किसी बाहुबली पर मेहरबानी करने का आरोप लग रहा हो, लेकिन ऐसा करने वाले नीतीश कुमार देश के इकलौते नेता नहीं हैं। यह सही है कि आनंद मोहन पर एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या का आरोप था। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में जब वह वह घटना हुई थी, तब शायद, उस भीड़ ने एक आईएएस को मारा था न कि किसी दलित को। भीड़ को शायद नहीं पता था कि जिस अधिकारी के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला किया जा रहा था वो किस बिरादरी का था।

हालांकि घटना बड़ी थी। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह से आनंद मोहन को सजा ही मिली थी। पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह आजीवन कारावास की सजा दी थी, यानी फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो गई थी। आनंद मोहन पिछले 14 साल से जेल में बंद थे। हालांकि बेटे की सगाई के लिए उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया है। अब आनंद मोहन कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जायेंगे।

नीतीश कुमार ने जेल नियमावली में बदलाव कर आनंद मोहन जैसे 26 कैदियों को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ कर दिया है। वर्षों से जो भी कैदी जेल में बंद थे, निश्चित तौर से वो शरीफ नहीं थे। वो हत्यारे थे । उनके बाहर आने से नीतीश कुमार को राजनैतिक फायदा कितना मिलेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन नीतीश कुमार को यह भी देखना पड़ेगा की बाहर आने के बाद उन कैदियों में सुधार होता है या नहीं। आनंद मोहन की रिहाई पर भाजपा कभी भी खुलकर नहीं बोल पाएगी। भाजपा ही नहीं, बिहार की कोई भी पार्टी आनंद मोहन के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पाएगी। क्योंकि सबको पता है कि आनंद मोहन के विरोध का मतलब बिहार के राजपूतों का विरोध करना हुआ।

नीतीश कुमार ने जो काम किया है उससे राजपूत कितने खुश होंगे यह देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने इस समय दो तरह की चुनौती उत्पन्न हो गई है। पहली यह कि जो लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, जो शायद आपराधिक मानसिकता के हैं, तो क्या नीतीश उन्हें अपराध करने से रोक पाएंगे? क्या जेल से छूटने वाले अपराधी बिहार में शांति व्यवस्था कायम रखने में नितीश कुमार का साथ देंगे? आखिरी और अहम् सवाल, क्या बिहार के राजपूत मतदाता नीतीश कुमार का साथ देंगे?

'विपक्षी एकता' एक सधी शुरूआत, कई क्षेत्रीय दल ही बनेंगे रोड़ा

हाजीपुर, 25 अप्रैल (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर कई नेताओं से मिलकर यह संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाएं तो नेता चुनने को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। माना जा रहा है कि नीतीश विपक्ष के एकजुट करने की सधी शुरूआत जरूर कर दी है, लेकिन क्षेत्रीय दल ही नहीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस आसानी से सबकुछ मान ले यह जरूरी नहीं।

नीतीश कुमार अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा सहित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिल चुके हैं।

इन नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने सभी नेताओं के एक साथ आने का दावा की बात कर रहे हैं। नीतीश सोमवार को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलने के बाद कहा कि हमलोगों के बीच पॉजिटिव बात हुई है। यह तय हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव के पहले पूरी तैयारी करें। सब लोग आपस में मिलकर बैठकर आगे की बात तय कर लेंगे।

कहा जा रहा है कि यह शुरुआत है और सभी लोग भाजपा को हटाने के मुद्दे पर एकसाथ आने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक न सीट बंटवारे की बात हो रही है और न ही नेता बनने की। जब इन बातों की चर्चा प्रारंभ होगी तब सही एकजुटता का पता चल सकेगा।

माना जा रहा है कि अब तक यूपीए का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस बडे भाई की भूमिका में है। ऐसे में जहां सीट बंटवारे की बात आएगी तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में खुद को कम आंकेगी यह आसान नहीं लगता। नेता के सवाल पर भी कांग्रेस किसी अन्य नामों के साथ समझौता करे इस पर भी सवाल उठता है।

राजनीति के जानकार अजय कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को यह पता है कि उसकी जमीन सिमटी है तो इन क्षेत्रीय दलों के कारण ही सिमटी है। ऐसे में वह किसी क्षेत्रीय दल के नेता को विपक्ष का नेता नहीं मानेगी।

भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद भी कहते हैं कि नीतीश कुमार से न अब अपनी पार्टी संभल रही है और नहीं बिहार संभल रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के एकजुट करने की बारत बेमानी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों की अपनी बड़ी बड़ी महत्वकांक्षा है। ऐसे में इन महत्वकांक्षा की पूर्ति में एक को खुश करने की कोशिश में दूसरा नाराज होना तय है।

इधर, कुमार कहते हैं कि नीतीश भले ही आज अपनी कोई महत्वाकांक्षा की बात नहीं कर रहे हों लेकिन नीतीश सियासत में कैसे खुद में बदलाव करते हैं, यह सबको पता है। ऐसे में केजरीवाल या ममता बनर्जी सहित किसी भी एक नाम पर सभी दलों को राजी करना आसान नहीं है।

भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता मनोज शर्मा कहते हैं कि नीतीश की विश्वसनीयता अब बिहार में ही समाप्त हो गई है। बिहार राज्य में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है जबकि केजरीवाल की पार्टी की दो राज्यों में सरकार है और ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत है।

शर्मा यहां तक कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस राजद के खिलाफ लड़ाई लडकर बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, उसी राजद के साथ मिलकर बिहार में वे सरकार बना चुके हैं। ऐसे में किसी भी दलों का उनपर विश्वास होगा यह उम्मीद नहीं है।

ऐसे में यह कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर सधी शुरूआत भाजपा के विरोधियों के लिए उत्साहित करने वाली बात है लेकिन क्षेत्रीय दलों में कब महत्वकांक्षा जोर मारने लगे, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है।

आनंद मोहन की रिहाई का फैसला असंवैधानिक : सुशील मोदी

पटना, 25 अप्रैल (का.सं.)। क्या बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल में बदलाव कर उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के पीछे नीतीश कुमार और लालू यादव की कोई राजनीतिक चाल है ? क्या आनंद मोहन के साथ जिन 26 अन्य अपराधियों को रिहा किया जा रहा है उससे आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में आरजेडी यो जेडीयू को फायदा पहुंचेगा ? क्योंकि सुशील कुमार मोदी का कहना है कि आनंद मोहन के साथ जिन 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है उनमें मुस्लिम यादव गठजोड़ का ध्यान रखा गया है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बहाने अन्य 26 ऐसे दुर्दांत अपराधियों को भी रिहा करने का फैसला किया है। जो मुस्लिम + यादव (एमवाई) समीकरण में फिट बैठते हैं और जिनके बाहुबल का दुरुपयोग चुनावों में किया जा सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि गंभीर मामलों में दोषसिद्ध अपराधियों की रिहाई का फैसला असंवैधानिक और अनाश्यक है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2016 में नीतीश सरकार ने ही जेल मैन्युअल में संशोधन किया था। नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर बलात्कर, आतंकी घटना, हत्या, बलात्कार के दौरान हत्या और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या को ऐसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा था। जिसमें कोई छूट या नरमी नहीं दी जाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जवाब दें कि अब किस आधार पर सरकार अपने ही संशोधित कानून को शिथिल कर रही है?

सुशील मोदी ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एससी-एसटी समुदाय के सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी को भी रिहा किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या और आनंद मोहन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के समय लालू प्रसाद ने पूर्व सांसद की कोई मदद नहीं की थी। ट्रायल शुरू होने पर यही ठंडा रवैया नीतीश कुमार का भी रहा। सुशील मोदी ने कहा कि आज आनंद मोहन के बहाने सरकार मानवीय होने का मुखौटा लगा कर जिन 27 अपराधियों को छोड़ने जा रही है। उनमें 7 ऐसे हैं, जिन्हें हर महीने स्थानीय थाने में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चलाने पर उनकी क्या मजबूरी है कि आनंद मोहन के साथ 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना पड़ रहा है।

आनंद मोहन को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर आईएएस लॉबी नाराज, सीएम नीतीश से पुनर्विचार को कहा

राजेश अलख

नई दिल्ली, 25 अप्रैल । आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले की आलोचना की है। इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (सेंट्रल) एसोसिएशन ने सोमवार को इस बाबत एक बयान भी जारी किया। इसमें एसोसिएशन ने बिहार सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह न्याय से इनकार करने के समान है।

इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (सेंट्रल) एसोसिएशन के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की नृशंस हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त करता है।

इसमें जोर देकर कहा गया है कि ड्यूटी पर एक लोक सेवक की हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को कम जघन्य श्रेणी में फिर से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जेल नियमावली के मौजूदा वर्गीकरण में संशोधन करना, जोकि एक लोक सेवक के सजायाफ्ता हत्यारे को रिहा करने की ओर ले जाता है, न्याय से दूर करने के समान है। इससे, लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है और सार्वजनिक व्यवस्था कमजोर होती है। साथ ही न्याय के प्रशासन का मजाक बनता है।

दरअसल, 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 (I) (क) बदलाव किया था। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल, बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था। बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को 26 अन्य लोगों के साथ रिहा किया गया है। वे 14 साल से अधिक समय से राज्य की विभिन्न जेलों में बंद हैं।

'डिप्टी सीएम बनते ही जांच एजेंसिया घर आ जाती हैं', तेजस्वी बोले- 2024 के लिए हो रही बड़ी तैयारी

मोतिहारी, 25 अप्रैल (नि.सं.)। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि जिसका बाप ईडी, सीबीआई से नहीं डरा उसका बेटा क्या डरेगा। जब-जब मैं बिहार के डिप्टी सीएम बनता हूं तब-तब जांच एजेंसियां मेरे घर पहुंच जाती हैं। तेजस्वी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का उन्होंने संकल्प लिया है। उसे पूरा करने के लिए मेरे पिता लालू यादव और बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी लगे हुए है। लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात हो रही है। बीते दिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मैंने और मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है।

तेजस्वी यादव ने ये बातें मोतिहारी में कहीं। वो कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के पिता व पूर्व विधायक स्व. यमुना यादव की पुण्यतिथि में जमुनिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सभी जाति, धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन भाजपा के लोग पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं। इस जाल में नहीं फंसना है और इसका जवाब 2024 में देना है।

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले महाराष्ट्र में खेला कर रहे थे,विधायक की खरीद फरोख्त कर रहे थे। बिहार में कब खेला हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। बिहार की सत्ता से कब बेदखल हो गए पता ही नहीं चला। तेजस्वी ने कहा कि भले आज हम पुण्यतिथि में आए है लेकिन आप सभी से एक अनुरोध करेंगे कि सभी एकजुट गोलबंद रहिए।जो समाज में दंग भड़काना चाह रहे हैं उससे सावधान रहना है।

विपक्ष को एकजूट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं सीएम नीतीश

हाजीपुर, 25 अप्रैल (का.सं.)। केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार यानी भाजपा के खिलाफ अगर कोई बहुत मुखर होकर विरोध कर रहा है, अगर कोई विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वह हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

हालांकि भाजपा के खिलाफ एकजुट होने या भाजपा का विरोध, देश की सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि बगैर किसी लालच या बगैर किसी स्वार्थ के, नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वह खुद भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें देश का प्रधान मंत्री नहीं बनना है, तो क्या मान लिया जाय कि नीतीश की निगाह कहीं और है? शायद विपक्ष की सरकार बनने के बाद उनकी निगाह राष्ट्रपति के पद पर हो!

इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव अन्य चुनावों से कहीं ज्यादा अलग होने जा रहा है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के सामने सत्ता को बचाये रखने की चुनौती है, तो विपक्ष के सामने अपने आपको बचाये रखने परीक्षा है। पिछले नौ साल से देश की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी को भाजपा एक बार फिर सत्ता पर काबिज करने का दावा कर रही तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब देख रहा है। सत्ता और विपक्षी पार्टियों के दावों के पीछे की सबकी अपनी-अपनी दलीलें हैं। भाजपा इस बात का दावा करा रही है कि प्रधान मंत्री मोदी के काम से पूरा देश खुश है, इसलिए उनकी फिर से सरकार बनने जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष यह दावा कर रह है की वर्तमान सरकार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कुछ नहीं कर पाई, इसलिए इस बार देश की जनता किसी और को सत्ता पर बिठाने का मन बना चुकी है।

2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति क्या होगी,उसकी चर्चा बाद में होगी। पहले बात नीतिश कुमार की। पूरे देश को पता है कि इस समय नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर विपक्ष के अन्य नेताओं से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। लगभग सात महीने पहले दिल्ली जाकर वो विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके थे। उस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, अरविन्द केजरीवाल, सीताराम येचुरी, शरद पवार समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। एक सप्ताह पहले भी वो दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। सभी नेताओं से उन्होंने बढ़िया से बात की थी। अभी सोमवार यानी 24 अप्रैल को उन्होंने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाक़ात की थी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद दोनों ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस भी की । इस दौरान पत्रकारों से बगैर पूछे ही नीतिश कुमार ने कह दिया कि उन्हें प्रधनमंत्री नहीं बनना है।

नीतीश प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना बनने की बात कई बार पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है की जब नीतिश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ही नहीं चाहते तो आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं?

दरअसल नीतीश कुमार इसी बहाने सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश सबका विश्वास जीतने का भी है। अपनी इसी पहल के दैरान वो अपनी स्वीकार्यता भी देख रहे हैं। संभव है कि जब इनकी सरकार बने तो सभी विपक्षी पार्टियां नितीश कुमार के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने लिए आसानी से तैयार हो जाएँ। यानी नीतीश कुमार कहीं न कहीं यह जरूर चाहेंगे कि उन्हें उनकी मेहनत का फायदा जरूर मिले, भले ही वो राष्ट्रपति के रुप में क्यों न हो। तो यह मान लेना चाहिए कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अगर कहीं विपक्ष की सरकार बन गई तो नीतिश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार होंगे।

केकेआर पर जीत के इरादे से उतरेगी आरसीबी

अहमदाबाद (एजेंसी)। बेंगलुरु (ईएमएस)। आईपीएल में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पर जीत के इरादे से उतरेगी। आरसीबी ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हराया था। ऐसे में वह बढ़े हुए मनोबल के साथ इस मैच में उतरेगी। आरसीबी को इसके साथ ही घरेलू हालातों का भी लाभ मिलेगा। वहीं विरोधी टीम केकेआर को पिछले चार मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इससे टीम पर मानसिक दबाव रहेगा जिससे उबरकर उसे मैदान में उतरना होगा। केकेआर का प्रयास किसी भी प्रकार इस मैच में आरसीबी को हराकर प्लेऑफ के ए अपनी संभावनाएं बनाये रखना रहेगा। केकेआर अभी तक सात मैचों में से केवल दो ही जीत पायी है और सातवें नंबर पर है। ऐसे में एक और हार उसपर भारी पड़ेगी।

केकेआर की टीम इस सत्र में अबतक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पायी है। उसे जो जीत मिली हैं उसमें भी एक दो बल्लेबाजों की ही अहम भूमिका रही है। टीम को पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में उसके कप्तान नितीश राणा सहित प्रमुख बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, और एन जगदीशन भी बड़ी पारी नहीं खेल पाये।

टीम अभी तक स्थायी सलामी जोड़ी तक नहीं तलाश पायी है। उसने अभी तक सुनील नारायण, जगदीशन, लिटन दास, जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरा पर कोई भी उसे अच्छी शुरुआत नहीं दे पाया। पिछले मैच में जेसन रॉय और रिंकू सिंह ने अर्धशतक लगाये पर इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। आद्रे रसेल भी फिनिशर की अपनी भूमिका में अब तक असफल रहे हैं।

टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस भी सही नहीं रही। इसी कारण उसके गेंदबाज अभी तक एक बार भी अपने कोटे के चारों ओवर नहीं कर पाए हैं। केकेआर ने इस सत्र की शुरुआत में आरसीबी पर बड़ी जीत दर्ज की थी। उसी प्रदर्शन को अब टीम दोहराना चाहेगी। दूसरी ओर आरसीबी अपने घरेलू मैदान पर जीत के लिए पूरी ताकत लगा देगी। की

आरसीबी की टीम अभी तक सात में से चार मैच जीतकर पांचवें स्थान पर है। उसके कुछ खिलाड़ियों ने अभी तक इस सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। डुप्लेसी अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने विराट कोहली तथा ग्लेन मैक्सवेल के साथ अच्छी साझेदारियां की हैं।

आरसीबी का कमजोर पक्ष से है कि अब तक उसके लिए कुछ ही खिलाड़ियों ने रन बनाये हैं जिससे वह जीत रही है। वहीं अन्य बल्लेबाज विफल रहे हैं। अब उसके मध्यक्रम के बल्लेबाजों से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। मध्यक्रम में दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, शाहबाज अहमद और सुयश प्रभुदेसाई अब तक अपेक्षा के अनुसार रन नहीं बना पाये हैं। उसके बल्लेबाजों को केकेआर के स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा और सुनील नरेन से सावधान रहना होगा।

वहीं गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने आईपीएल के वर्तमान क्षेत्र में अभी तक सबसे अधिक विकेट लिए हैं। सिराज का वायने पर्नेल और हर्षल पटेल ने अच्छा साथ दिया है। वहीं श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा के जुड़ने से टीम की गेंदबाजी बेहतर हुई है। कुल मिलाकर देखा जाये तो ये मुकाबला रोमांचक होगा।

संभावित प्लेइंग 11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : विराट कोहली (कप्तान), फाफ डु प्लेसिस , महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज़ अहमद, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), सुयश प्रभुदेसाई, डेविड विली, वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद सिराज, विजयकुमार वैशाक, हर्षल पटेल।

कोलकाता नाइट राइडर्स : नितीश राणा (कप्तान), एन जगदीसन (विकेटकीपर), जेसन रॉय, आद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, डेविड विसे, शार्दुल ठाकुर, सुयश शर्मा, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती।

बजरंग पूनिया का आरोप, पहलवानों को शिकायत वापस लेने पैसे की पेशकश हो रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। ओलंपियन पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि पहलवानों को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) से जुड़े कुछ लोगों ने पैसे का लालच दिया है। जिससे वे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी धरने से हट जायें। बजरंग सहित कई पहलवान अभी बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बजरंग ने यह भी आरोप लगाया कि यौन शोषण का शिकार हुई एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों को पुलिस बृजभूषण के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रही है। बजरंग ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के कुछ लोगों ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें पैसे की पेशकश भी की है।

पुनिया ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ पर जिन लड़कियों ने शिकायत की है उन पर दबाव डाला जा रहा है। कुश्ती महासंघ के अधिकारी उनके घर जाकर पैसे का लालच दे रहे हैं। अगर उन लड़कियों के साथ कुछ होता है, तो पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी। मुझे नहीं पता कि नामों का खुलासा कैसे हुआ।

वहीं इससे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज न किए जाने का आरोप लगाने वाली पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक इस मामले में अपना जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये गंभीर आरोप' हैं जिन पर विचार करने की जरुरत है। वहीं पहलवानों ने आरोपों की जांच करने वाली समिति के परिणामों को सार्वजनिक करने की मांग भी की है।

बेंगलुरु दौड़ की अंतरराष्ट्रीय दूत होगी सान्या रिचर्ड्स रॉस

बेंगलुरु (एजेंसी)। पूर्व ओलंपिक और 400 मीटर में विश्व चैंपियन सान्या रिचर्ड्स रॉस को 21 मई को यहां होने वाली विश्व 10 किमी बेंगलुरु दौड़ का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा दूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका की एथलीट सान्या रिचर्ड्स रॉस विश्व एथलेटिक्स की नामी खिलाड़ियों में शामिल है। वह ओलंपिक में लगातार तीन बार चार गुणा 400 मीटर रिले दौड़ जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला एथलीट हैं। जमैका में जन्मी सान्या रिचर्ड्स रॉस ने ओलंपिक तथा विश्व चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 14 पदक जीते हैं।

इसके अलावा विश्व रिले में उनके नाम पर तीन स्वर्ण पदक दर्ज है। उन्होंने डायमंड और गोल्डन लीग में भी कई पदक जीते हैं। सान्या रिचर्ड्स रॉस ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा,'' मैं टीसीएस विश्व 10 किमी बेंगलुरु का हिस्सा बनकर रोमांचित हूं। भारत में इस तरह की दौड़ तेजी से विकास कर रही है और मैं 2018 में देश के पिछले दौर के दौरान दिल्ली में इसकी गवाह रह चुकी हूं।

तो अब अर्जुन तेंदुलकर फेकेंगे 140किलोमीटर की स्पीड से गेंद, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने दिया सचिन के बेटे को सुझाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई इंडियंस की टीम के गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर ने इसी सीजन में अपना आईपीएल डेब्यू किया है। पहले ही सीजन में उन्होंने काफी शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए एक ही ओवर में 31 रन लुटाए जिसके बाद उन्हें चौरफा आलोचना का शिकार होना पड़ा था। इस मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने काफी खराब परफॉर्म किया था।

इस तरह खराब प्रदर्शन करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज खिलाड़ी ब्रेट ली ने भी अर्जुन तेंदुलकर को खास हिदायत दी है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली ने अर्जुन के समर्थन में आकर उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करने के तरीके को लेकर खास टिप्स दिए है। ब्रेट ली ने हाल ही में कहा कि मैं अर्जुन तेंदुलकर के खेल से काफी प्रभावित हूं। मुंबई इंडियंस के लिए अर्जुन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वो नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करता है। उसमें गेंद को स्विंग करने की क्षमता भी है।

उन्होंने कहा कि अर्जुन तेंदुलकर गेम को एंजॉय करते हुए डेथ ओवर में शानदार खेल दिखाता है। ऐसे में उसकी तारीफ करना जरुरी है। ब्रेट ली ने लोगों द्वारा की जा रही टिप्पणियों को लेकर कहा कि लोगों

का काम आलोचना करना है। आलोचना हर मैच में हर कदम पर होगी। अर्जुन के लिए जरुरी है कि वो आलोचकों की बातों को नजरअंदाज करें। उन्होंने कहा कि अर्जुन तेंदुलकर की उम्र अभी सिर्फ 23 वर्ष है।

ऐसे में अपने लंबे करियर को ध्यान में रखते हुए उन्हें आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके पिता के साथ भी करियर के शुरुआती दौर में यही सब हुआ था। अगर अर्जुन टीम में घुलेंगे तो वो जल्द ही 140 किलोमीटर की रफ्तार से भी गेंद फेंकने में सक्षम होंगे। उनकी स्पीड के साथ किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आती है। ऐसे में अर्जुन को सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए। बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने इसी वर्ष 16 अप्रैल को अपना आईपीएल डेब्यू किया है। उन्होंने अपना पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था। अबतक वो तीन मुकाबले खेल चुके है जिनमें उन्होंने दो विकेट झटके है। उनका इकॉनमी रेट 10.6 का रहा है।

लारा ने हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार बताया

हैदराबाद (ईएमएस)। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच ब्रायन लारा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के लिए टीम के बल्लेबाजों को जिम्मेदार बताया है। लारा ने कहा कि बल्लेबाज छोटे लक्ष्य का पीछा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों ने कमजोर गेंदों पर भी बड़े शॉट नहीं खेल पाये ओर आक्रामक रुप अपनाने में उन्होंने काफी देर कर दी थी। उन्होंने कहा कि अपने रक्षात्मक रुख का सनराइजर्स के बल्लेबाजों को नुकसान उठाना पड़ा है। लारा ने कहा, 'पिच में किसी तरह की कमी नहीं थी और हमें पूरी पारी के दौरान तेजी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, 'हमने सब कुछ अंतिम ओवरों के लिए छोड़ दिया जिसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर हमारे बल्लेबाज पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते तो परिणाम कुछ और होता। इससे विरोधी टीम बीच के ओवरों में हावी हो गयी। उन्होंने कहा कि टीम पावर प्ले में 36 रन ही बना पायी। लारा ने कहा, 'पहले 15 ओवर काफी अहम होते हैं और उसमें हमें काफी अच्छी स्थिति में होना चाहिए था। सनराइजर्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। लारा ने कहा, 'हमें अब आगे के बारे में सोचना होगा और जल्द ही एक ईकाई के तौर पर प्रदर्शन करना होगा। अब हमारे लिए राह कठिन है, इसलिए हमें और हमें अधिक जिम्मेदारी से खेलना होगा।

शोएब ने सानिया से तलाक की खबरों को निराधार बताया

लाहौर । पिछले काफी समय से भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक की अटकलें लगायी जा रहीं थीं पर अब शोएब ने इन खबरों को आधारहीन बताया है। शोएब ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण ही वे दोनो पिछले काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं। एक टीवी चैनल पर ईद के विशेष शो में मलिक ने कहा कि वह और उनकी पत्नी सानिया किसी भी तलाक की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे और न ही वे अलग हुए थे। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी और बेटा ईद पर बाहर हैं। काश मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ ईद मना पाता। इस क्रिकेटर ने माना कि सभी शादियां उतार-चढ़ाव से गुजरती हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि रिश्ता समाप्त हो गया। मलिक ने बताया कि दोनों को कुछ समय के लिए एक साथ इसलिए नहीं देखा गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से दोनों का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण उन दोनो के लिए एक साथ समय बिताना कठिन हो गया है पर कहा कि उनके अलग होने और मतभेदों की खबरें गलत हैं। वहीं दूसरी ओर सानिया ने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारतीय टीम का ऐलान

रहाणे की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले के लिए भारतीय टीम में वापसी

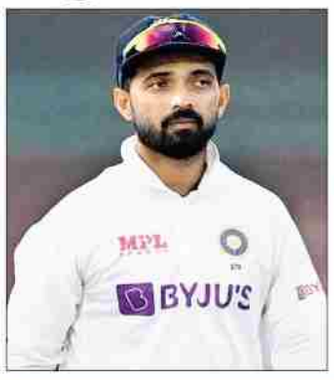

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में सात जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के खिताबी मुकाबले के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है। रोहित शर्मा की कप्तान वाली इस टीम में बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। रहाणे को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का ईनाम मिला है और लंबे समय के बाद उन्हें टीम में जगह मिली है। रहाणे ने आईपीएल के इस सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। रहाणे ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए मुंबई और कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ तेज अर्धशतक लगाये।

रहाणे ने अंतिम बार भारतीय टीम की ओर से करीब डेढ़ साल पहले जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उसके बाद खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें पहले उपकप्तानी और उसके बाद टीम से ही बाहर कर दिया गया था। पिछले कुछ समय में रहाणे ने घरेलू क्रिकेट और उसके बाद आईपीएल में अपने अच्छे प्रदर्शन से टीम में वापसी की दावेदारी पेश की थी।

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराते हुए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनायी है।

टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मो. शमी, मो. सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकत।

छक्के मारने में डु प्लेसिस , चौके में वार्नर सबसे आगे

मुम्बई । आईपीएल के इस 16 वें सत्र में अब तक कई नये रिकार्ड बने हैं। इस बार सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में पहले स्थान पर आरसीबी के फॉफ डु प्लेसिस हैं। डु प्लेसिस ने अभी तक खेले 7 मैचों में 25 छक्के लगाये हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आरसीबी के ही ग्लेन मैक्सवेल हैं। उनके नाम 23 छक्के हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर चेन्नई सुपरकिंग्स के रितुराज गायकवाड़ हैं। उनके नाम 17 छक्के हैं। लखनऊ सुपर जायंटस के काकाइ मायर्स 16 छक्के लगाकर पांचवे नंबर पर हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर पहले स्थान पर हैं। वार्नर के नाम 42 चौके हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सीएकके के कप्तान डु प्लेसिस के नाम 33 चौके हैं। वहीं सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर सीएसके के डेवोन कॉन्वे के नाम 32 चौके हैं। राज्स्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल के नाम भी 32 ओर पंजाब के शिखर धवन के नाम 29 चौके हैं।

विश्व शतरंज चैंपियनशिप : राउंड 11 : नेपोमनिशी 6-5 से हुए आगे , विश्व खिताब से 1.5 अंक दूर

अस्ताना, कज़ाकिस्तान । विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ग्यारवें राउंड में बढ़त पर चल रहे रूस के यान नेपोमनिशी नें सफ़ेद मोहरो से संतुलित खेल दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंदी चीन के डिंग लीरेन को वापसी का फिर से कोई मौका नहीं दिया और मैच बिना किसी जीत हार के बेनतीजा रहा , इस परिणाम के बाद नेपोमनिशी अब 14 राउंड की विश्व चैंपियनशिप में 6-5 से आगे चल रहे है और अब उन्हे विश्व खिताब हासिल करने के लिए 1.5 अंको की और आवश्यकता है वहीं डिंग के लिए लगातार जीत ही उन्हे विश्व खिताब दिला सकती है । बचे हुए तीन राउंड में डिंग के पास दो बार सफ़ेद मोहरे तो एक बार काले मोहरे होंगे । ग्यारहवें राउंड में नेपो नें राय लोपेज ओपनिंग का क्लोस वेरिएशन खेलते हुए और खेल की आठवीं चाल में हाथी के सामने का प्यादा एक घर चलकर 3 साल पहले डिंग के खिलाफ जीती गयी बाजी को दोहराने की कोशिश की जिसे डिंग नें चाल बदलकर जबाब दिया और लगातार मोहरो की अदला बदली की बीच बाजी 39 चालों के बाद ड्रॉ रही ।अब एक दिन के विश्राम के बाद अगले दो राउंड खेले जाएँगे।

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 में मचाया धमाल, हासिल किया खास मुकाम मगर टीम को नहीं दिला सके जीत

नयी दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अपने खेल के दम पर फिर से खुद को साबित किया है कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की सूची में शामिल होने के पूरे काबिल है। रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवे टी20 मुकाबले में खेल कर साबित किया है कि वो शानदार खिलाड़ी है। इस मुकाबले में उनके बल्ले से बेहतरीन अर्धशतक निकला है।

इस मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ने दमदार खेल दिखाया मगर टीम को जीत नहीं दिला सके। इसके साथ ही उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शानदार रिकॉर्ड भी हासिल किया है। बता दें कि रिजवान विकेटकीपर के तौर पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए है। उन्होंने इंग्लैंड के जोस बटलर को पछाड़ कर ये उपलब्धि हासिल की है।

बता दें कि ये मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया था जहां पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 193 रन बनाए। ओपनिंग करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 62 गेंद में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 98 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि वो अपने टी20 करियर का दूसरा शतक से दो रन से चूक गए।

बराबर पर खत्म हुई सीरीज

मार्क चैपमैन के करियर के पहले शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 2-2 के बराबर की। न्यूजीलैंड के सामने 194 रन का लक्ष्य था लेकिन 10वें ओवर तक उसका स्कोर चार विकेट पर 73 रन था। चैपमैन ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 57 गेंदों पर 11 चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 104 रन बनाए तथा जेम्स नीशम (25 गेंदों पर नाबाद 45) के साथ पांचवें विकेट के लिए नौ ओवर में 121 रन की अटूट साझेदारी की।

इससे न्यूजीलैंड ने 19.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर पांच विकेट पर 193 रन बनाए थे। उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 62 गेंदों पर नाबाद 98 रन बनाए जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज के अलावा इफ्तिखार अहमद ने 36 और इमाद वसीम ने 31 रन का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिए ब्लेयर टिकनर ने 33 रन देकर तीन विकेट लिये।

न्यूजीलैंड के लिए यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके प्रमुख खिलाड़ी

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया। न्यूजीलैंड की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह 100वीं जीत है। दोनों टीमों के बीच अब पांच मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी जिसका पहला मैच गुरुवार को रावलपिंडी में होगा।

पिंडली की चोट के कारण टेनिस टूर्नामेंट से हटी ओंस जाबूर

मैड्रिड। गत चैम्पियन ओंस जाबूर बायीं पिंडली में चोट के कारण मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गई है जिससे उनकी फ्रेंच ओपन की तैयारियों को करारा झटका लगा है। ट्यूनीशिया की विश्व में चौथे नंबर की खिलाड़ी जाबूर ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में चल रहे क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में तब मैच से हटने का फैसला किया जब वह विश्व की नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वियातेक के खिलाफ पहलेसेट में 0-3 से पीछे चल रही थी। जाबूर ने इसके बाद ट्विटर पर पोस्ट किया कि उनकी पिंडली चोटिल हो गई है और उन्हें कई तरह की जांच करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा,'' मुझे इस चोट से उबरने के लिए समय चाहिए। मुझे यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि मैं मैड्रिड में नहीं खेल पाऊंगी।'' जाबूर पिछले साल विंबलडन और अमेरिकी ओपन में उपविजेता रही थी। उन्हें पिछले साल फ्रेंच ओपन में खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन वह पहले दौर में हारकर बाहर हो गई थी। फ्रेंच ओपन 28 मई से पेरिस में शुरू होगा।

मुस्लिमों के 4 फीसदी आरक्षण मामले में सुनवाई 9 मई तक स्थगित, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत कोटा खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला नौ मई तक जारी रहेगा। नौ जुलाई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।

राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे।

उन्होंने पीठ से कहा, मैं इसे आज दाखिल करूंगा लेकिन समस्या यह है कि मैं (सॉलिसिटर जनरल) व्यक्तिगत समस्या का सामना कर रहा हूं। मुझे समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सामने भी दलील रखनी है। कृपया इस मामले को किसी और दिन के लिए सूचीबद्ध करें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई पहले ही चार बार टाली जा चुकी है।

मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है।

दवे ने अदालत से अनुरोध किया कि वह मेहता की दलीलों को दर्ज करें कि मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और 30 मार्च 2002 को जारी किया गया आरक्षण देने का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा।

पीठ ने दवे के साथ सहमति व्यक्त की और आगे की सुनवाई के वास्ते मामले को नौ मई के लिए सूचीबद्ध किया।

उच्चतम न्यायालय ने 18 अप्रैल को कर्नाटक में मुसलमानों का चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। तब भी राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था।

उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल को कहा था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो प्रतिशत वृद्धि करने एवं ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया 'त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। राज्य में 10 मई को चुनाव हैं।

कर्नाटक सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक 24 मार्च के सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति और दाखिला नहीं दिया जाएगा।

कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों के लिए चार फीसदी कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की दो नयी श्रेणियों की घोषणा की थी। ओबीसी मुसलमानों के चार फीसदी कोटे को वोक्कलिगा और लिंगायत समुदायों के बीच बांट दिया गया है। यही नहीं, आरक्षण के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत कर दिया गया है।

राज्य सरकार के फैसले के बाद अब वहां आरक्षण की सीमा करीब 57 फीसदी हो गई है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है।

पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया, 13 गिरफ्तार

हैदराबाद, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना और अन्य राज्यों में नकली भारतीय नोटों का कारोबार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने 13 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है और 30.68 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट जब्त किए हैं।

संयुक्त अभियान में, स्पेशल टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस टीम (एसओटी) साइबराबाद के अधिकारियों ने गिरोह को पकड़ा और 60,500 रुपये के नोट और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किए। मुख्य आरोपी कोनेती राजेश और नील दास ओडिशा और त्रिपुरा के रहने वाले हैं। अन्य आरोपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रहने वाले हैं।

तमिलनाडु के सूर्या समेत तीन अन्य आरोपी फरार हैं। रायदुर्गम पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक होटल सुपरवाइजर की शिकायत पर यह सफलता मिली कि एक ग्राहक राजेश ने कमरा खाली करते समय जाली नोट दिए थे। पुलिस जांच में पता चला कि राजेश और कुछ अन्य लोगों ने एक गिरोह बना लिया था और नकली नोटों को चोरी-छिपे छाप कर बांट रहे थे।

आरोपी राजेश यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करता था और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था कि नकली मुद्रा उपलब्ध है और अकाउंट डीपी में मोबाइल नंबर देता था जिसके माध्यम से अलग-अलग ग्राहक उसके संपर्क में आते हैं और नकली नोट खरीदते हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि नकली मुद्रा के प्रचलन के लिए विभिन्न निर्माताओं और वितरकों द्वारा एक ही मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है।

राजेश और नील दास विभिन्न नकली मुद्रा आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं जैसे तेलंगाना के रमेश, चरण सिंह और आंध्र प्रदेश के गिरोह और तमिलनाडु के सुरिया के संपर्क में आए। उनसे 1:5 के अनुपात में नकली नोट ले गए। गिरोह के मुख्य सदस्य राजेश और नील दास गिरोह के अन्य सदस्यों को 1:3 के अनुपात में यह कहकर नकली नोटों की आपूर्ति करते थे कि ये नोट मूल मुद्रा के समान हैं। आरोपी ने जिन लोगों को नकली नोट सख़लाई किया, उनसे रात के बाजारों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटी दुकानों में नोटों का इस्तेमाल करने के लिए कहा।

पुलिस के अनुसार, गांवों में छोटी किराने की दुकानों, साप्ताहिक सब्जी बाजारों, पान की दुकानों, शराब की दुकानों, पेट्रोल पंपों, चावल मिलों, इंटरनेट केंद्रों पर मनी ट्रांसफर की दुकानों, दूध की दुकानों, आयोजनों और कॉलेज उत्सवों, कबाड़ की दुकानों, ठेलागाड़ियों और लेबर अड्डों में अत्यधिक प्रचलित हैं।

बीजेपी की सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा घोटाला किया : अखिलेश

लखनऊ, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों की समस्या भाजपा की देन है। कानपुर, वाराणसी और आगरा सहित बड़े शहरों में भाजपा के ज्यादातर मेयर हैं।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 'मंगलवार को कहा कि शहरों की समस्या भाजपा की देन है। कानपुर, वाराणसी और आगरा सहित बड़े शहरों में भाजपा के ज्यादातर मेयर हैं। भाजपा ने कोई स्मार्ट सिटी को लेकर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। राजधानी का हाल बेहाल है। अयोध्या में मेयर का टिकट इसलिए भाजपा ने काट दिया। क्यों कि वहां जमीन की रजिस्ट्री के नाम गड़बड़ी के आरोप है। शाहजहांपुर में भाजपा के पास मेयर प्रत्याशी नहीं है।'

उन्होंने कहा कि शहरों में पार्कों को भाजपा ने बर्बाद कर दिए हैं। गोमती नदी में खुले में नाले गिर रहे हैं। लखनऊ समेत बड़े शहर जाम से जूझ रहे हैंक पीएम मोदी ने कूड़े से बिजली बनाने के लिए कहा था। मगर कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ।

बोले कि, 'मेरे गाने को एडिट कर भाजपा ने ट्वीट कर जनता को मुद्दों से भटकाने चाहती है। स्मार्ट सिटी में जलापूर्ति, 24 घंटे बिजली, गरीबों के आवास ,नागरिक सुरक्षा, हेल्थ, शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा खेल कर रही है। वहीं,उमेशपाल और अतीक हत्याकांड के सवाल पर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था फेल है।

उन्होंने कहा 'समाजवादी सरकार में जो काम हुआ। उसे सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए केवल दो बार मीटिंग हुई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लखनऊ मेट्रो कानपुर मेट्रो आगरा मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ गया।

कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे : अमित शाह

बागलकोट, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वह दंगों की चपेट में रहेगा।

शाह ने कहा कि कांग्रेस के सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास रिवर्स गेयर में चला जाएगा।

कर्नाटक में लोगों से राजनीतिक स्थिरता के लिए मतदान करने की अपील करते हुए शाह ने इस जिले के तेरदल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ही राज्य को नया कर्नाटक बनाने की दिशा में आगे ले जा सकती है।

पार्टी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकारों तथा प्रचारकों में से एक शाह ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों की चपेट में रहेगा।

शाह ने कहा, अगर कांग्रेस गलती से सत्ता में आ जाती है तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा और तुष्टीकरण होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के फैसले का मंगलवार को बचाव करते हुए कहा कि पार्टी ने कभी धर्म आधारित आरक्षण में विश्वास नहीं किया।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर आरक्षण बहाल करने के कांग्रेस के रुख पर भी निशाना साधा. शाह ने तेरदल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण धर्म आधारित था। वोट बैंक की राजनीति में पड़े बिना भाजपा सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए. मंत्री ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के बाद भाजपा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया है। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई नीत सरकार के अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि एससी (लेफ्ट) के लिए अब छह प्रतिशत आरक्षण है, एससी (राइट) 5.5 प्रतिशत और अन्य एससी समुदाय के लिए 5.5 प्रतिशत आरक्षण है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार के उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने के वादे पर शाह ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि वह सरकार बनाने पर किस समुदाय का आरक्षण खत्म करेंगे। मंत्री ने पूछा, मुसलमानों का चार प्रतिशत आरक्षण बहाल करने के लिए किस का आरक्षण खत्म किया जाएगा? क्या वे वोक्कालिगा या लिंगायत, दलित, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग होगा?

अपने कार्यकाल के अंत में भाजपा सरकार ने 2-बी श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय किया है। इस चार प्रतिशत आरक्षण में से वोक्कालिगा को 2-सी श्रेणी का दो प्रतिशत आरक्षण और लिंगायत को 2-डी श्रेणी का दो प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

वोक्कालिगा और लिंगायत कर्नाटक के दो प्रभावशाली समुदाय हैं। शाह का यह बयान ऐसे दिन आया है, जब उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा।

शाह अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जनसभाओं, रोड शो और समीक्षा बैठकों के लिए कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना की जाएगी।

महिला पहलवानों और उनके परिवारों को धमकियां मिल रही हैं : विनेश फोगाट

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के कुछ अधिकारी महिला पहलवानों को धमका रहे हैं और उन्हें डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि सात महिला पहलवानों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विनेश ने आईएएनएस से कहा, उनके (शिकायतकर्ताओं) परिवार के सदस्यों को अब धमकियां मिल रही हैं। उनकी जान को खतरा है। पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और निर्दोष लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर इन शिकायतकर्ताओं को कुछ होता है, तो इसके लिए दिल्ली पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी।

रविवार को बजरंग पुनिया, विनेश और साक्षी मलिक सहित देश के शीर्ष पहलवान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल पर फिर से बैठ गए और डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। वह यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक करना चाहिए, जिसने बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की थी।

विनेश ने तीन महीने पहले बृजभूषण के विरोध के बावजूद खेल मंत्रालय द्वारा कार्रवाई करने में विफल रहने पर निराशा व्यक्त की। विश्व चैम्पियनशिप की पदक विजेता ने जोर देकर कहा, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सरकार को कितना समय लगने वाला है? हम अभी भी उनसे सुनने का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, इस बार हम यहां तब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें हर जगह से समर्थन मिल रहा है। और हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो यहां मौजूद हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि भारत में एथलीटों के बेहतर भविष्य के लिए आएं और हमारा समर्थन करें। यह सभी महिला एथलीटों की लड़ाई है और उन्हें आगे आकर अपने विचार साझा करने चाहिए।

सरकार ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने के आरोपों की जांच के लिए 23 जनवरी को छह सदस्यीय पैनल का गठन किया था। पैनल ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी लेकिन सरकार ने यह कहते हुए अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया कि यह अभी भी जांच के अधीन है।

महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यौन उत्पीड़न के आरोपियों को प्रोत्साहित करता है पुलिस का रवैया

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेन्सी)। सात महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह जरुरी है कि पुलिस यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को गंभीरता से ले और तुरंत एफआईआर दर्ज करे। हालांकि, शिकायतकर्ताओं के प्रति पुलिस का रवैया चौंकाने वाला था।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की मांग करने वाली पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि हमारे देश को गौरवान्वित करने वाली महिला एथलीटों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और जिस समर्थन की वे हकदार हैं, उसे पाने के बजाय उन्हें न्याय पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया कि इस मामले में आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। मामले से बचने के लिए वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है और न्याय में बाधा डाल रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह जरूरी है कि पुलिस यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को गंभीरता से ले और तुरंत एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करने में देरी कर एक और बाधा पैदा न करें।

एफआईआर दर्ज करने में देरी न केवल पुलिस विभाग की विश्वसनीयता को कम करती है बल्कि यौन उत्पीड़न के अपराधियों को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे महिलाओं के लिए आगे आना और ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करना अधिक कठिन हो जाता है।

याचिका में कहा गया, तीन दिन बीत जाने के बावजूद, यानी 21-24 अप्रैल तक, दिल्ली पुलिस द्वारा कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। यह स्पष्ट रूप से मामलों की एक दुखद स्थिति और मानवाधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, विशेष रूप से उन लोगों की जो सबसे कमजोर हैं। पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रही है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 21 अप्रैल को वे अपनी औपचारिक लिखित शिकायत लेकर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने शिकायतें लीं और लगभग तीन घंटे तक शिकायत की औपचारिक रसीद भी जारी नहीं की।

आगे कहा गया, पुलिस अधिकारी अपने मोबाइल पर शिकायतों की तस्वीरें लेते और उन्हें इधर-उधर भेजते देखे गए। शिकायतकर्ताओं के प्रति पुलिस का रवैया चौंकाने वाला था। यह अन्याय है और उनके मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

दलील में कहा गया है कि कई मौकों पर आरोपी और उसके करीबी सहयोगियों द्वारा यौन, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक शोषण के बाद, याचिकाकर्ताओं ने अन्य पहलवानों के साथ इस तरह के कृत्यों के खिलाफ उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपनी आवाज उठाने का साहस जुटाया और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए।

इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आरोपों के मद्देनजर, 23 जनवरी के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर

आरोपों की जांच के लिए 5 मेंबर्स वाली ओवरसाइट कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया था।

ओवरसाइट कमेटी ने आरोपों पर ध्यान दिया और पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि, यह जानकर दुख होता है कि समिति के गठन के बावजूद इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

इसके अलावा, प्रिंट मीडिया के अनुसार, यह चलन में है कि वास्तव में आरोपी को मामले में क्लीन चिट दे दी गई है और समिति की रिपोर्ट खेल मंत्रालय में पड़ी हुई है और अनुरोध के बावजूद रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत के शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करने की संभावना है।

डियर साप्ताहिक लॉटरी
गंगटोक निवासी ने
₹1करोड़ जीते

गंगटोक, सिक्किम के श्री विजय कुमार सिंह ने 02.02.2023 को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नम्बर 46J 41267 है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। "डियर लॉटरी से एक करोड़ रुपए पुरस्कार राशि जीतना मेरे लिए एक आश्चर्य बन गया है। मुझे एक करोड़पति बनाने के लिए डियर लॉटरी तथा नागालैंड स्टेट लॉटरीज को मेरे हृदय से धन्यवाद। यह केवल कुछ रुपए खर्च करने के द्वारा ही हो गया है।" विजेता ने कहा। डियर लॉटरी के ड्रॉ लाइव दिखाये जाते हैं।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com